छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 50 ■ अम्बिकापुर, मंगलवार 10 फरवरी 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

फ्लैक्स के कारोबारी से सादे चेक में हस्ताक्षर कराने के बाद 1.93 लाख रुपये आहरण

खुद को फायनेंस कम्पनी का कर्मचारी बताकर ओवर ड्राफ्ट खाता खोलने का दिया था झांसा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। फ्लैक्स का कारोबार करने वाले युवक के साथ पहुंचे कथित श्री राम फायनेंस के कर्मचारी ने सिविल स्कोर अच्छा होना बताते हुए ओवर ड्राफ्ट खाता खोलने का झांसा दिया और दो कैंसल चेक लेने के बाद दो अन्य सादे चेक में धोखे से हस्ताक्षर लेकर एक लाख 93 हजार 700 रुपये खाते से आहरण कर लिया। धोखाधड़ी का पता चलने पर कारोबारी ने कोतवाली थाने में घटना की जानकारी दी है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के केनाबांध बौरीपारा का सूर्यनारायण विश्वकर्मा प्रतापपुर नाका चौक में सूरज फलैक्स नाम से अपने कारोबार का संचालन करता है। दो फरवरी को जब वह दुकान में था तभी उसके मोबाइल नंबर पर अनजान व्यक्ति ने फोन करके अपना परिचय श्रीराम फायनेंस के कर्मचारी के रूप में दिया और कहा कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। उक्त व्यक्ति श्री राम फायनेंस कम्पनी का ऑफर बताते हुए कम ब्याज दर पर ओव्हर ड्राफ्ट एकाउंट खोलने का झांसा दिया। फ्लैक्स के कारोबारी ने किसी प्रकार का एकाउंट खोलवाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुन: 03 फरवरी को उसके मोबाइल फोन में कॉल आया। कॉल करने वाले ने उसे पुन: स्कीम के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कंपनी के मैनेजर से बात कराने के लिए कहा, जिस पर वह शाखा प्रबंधक से बात कराया। फोन रिसीव किए व्यक्ति ने अपना परिचय श्री राम फाइनेन्स के मैनेजर के रूप में दिया और अपने घुमावदार बातों में लेकर वह फ्लैक्स के कारोबारी को भ्रमित कर दिया, और वह उसके झांसे में आ गया। शाखा प्रबंधक से बात करने के बाद साइड विजिट के नाम पर पुन: मोबाइल पर फोन आया और 05 फरवरी को वह जरूरी कागजात लेने के लिए आ गया। कागजातों में हस्ताक्षर करते वक्त संबंधित व्यक्ति अपनी बातों में फंसाकर दो चेक कैंसल लिखकर सील व साइन करा लिया, और चेक ठीक तरह से नहीं फटने की बात कहते हुए दो चेक को अच्छी तरह से फाड़ने कहा। चेक को फिर से फाड़ने के बाद कारोबारी कागजातों में हस्ताक्षर कर रहा था। हस्ताक्षर अच्छे से करने की नसीहत देते वह कारोबारी को धोखे में रखकर दो नए चेक पर भी सील व साइन करा लिया। चेक को आधा मोड़कर हाथ से दबाने के कारण उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि सादे चेक पर वह सील व साइन करा लिया है। इसके बाद चेक क्रमांक 525698 से 95 हजार 700 रुपये एवं चेक क्रमांक 525631 से 98 हजार रुपये आहरण कर लिया। इसके अलावा सील व साइन किया हुआ एक चेक क्रमांक 525699 चेक भी जालसाज के पास है, जिससे और रुपये आहरण की आशंका बनी हुई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने कथित फायनेंस कर्मचारी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है, पुलिस मामले में अग्रिम पड़ताल कर रही है।

शराब दुकान में नौकरी लगवाने के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी

अंग्रेजी शराब दुकान में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवक से डेढ़ लाख रुपये की ठगी के बाद गाली-गलौज और मारपीट करने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम रनपुर खुर्द निवासी लोचन प्रसाद पिता कन्हैया लाल राजवाड़े 25 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि ग्रेजुएट तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह वर्तमान में बेरोजगार है। उसके मौसी का लड़का ओमप्रकाश राजवाड़े का संदीप गुप्ता पिता विजय गुप्ता निवासी ग्राम कांतिप्रकाशपुर, लुचकी से एक ही मोहल्ले में रहने के कारण जान-पहचान है। संदीप इसका फायदा उठाते हुए ओम प्रकाश से बोला कि अपने भाई का कहीं नौकरी क्यों नहीं लगवा देते हो। इस पर ओम प्रकाश बोला कि आजकल नौकरी आसानी से मिलता कहां है। संदीप उसे झांसे में लिया और कहा कि उसके फूफा दुकान में शराब सप्लाई करते हैं, उनसे बात करके तुम्हारे भाई का नौकरी अंग्रेजी शराब दुकान में लगवा दूंगा, लेकिन 1 लाख 50 हजार रुपये लगेगा। भाई का नौकरी लग जाएगा, सोचकर उसके झांसे में आ गया और 10,000 रुपये संदीप के मोबाइल नंबर पर फोन पे के माध्यम से 07.09.2024 को और 10.09.2024 को 1 लाख 40 हजार रुपये नकद दे दिया। उक्त राशि प्राप्त करने के बाद संदीप ने एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र मिल जाने की बात कही। एक सप्ताह के भीतर नौकरी नहीं लगने पर जब वे संदीप से संपर्क किए तो अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है कहते हुए वह टालमटोल करने लगा, और 15 दिन बाद नौकरी लग जाने की बात कहा। 15 दिन बाद भी नौकरी नहीं लगी, और वह नौकरी लगवाने का मात्र आश्वासन देते रहा। नौकरी नहीं लगने पर जब वह दिए गए रकम को वापस मांगा तो संदीप कहा कि आबकारी विभाग का डी.ओ. को पैसा दे दिया हूं, जब वो देंगे तब दूंगा। लगातार डेढ़ लाख रुपये वापस करने के लिए कहने पर वह 10 दिन बाद रकम वापस कर देने के लिए कहा। समय बीत गया, और रुपये वापस नहीं मिला तो बेरोजगारी की मार झेल रहा लोचन प्रसाद अपने भाई ओमप्रकाश के साथ रुपये लेने के लिए संदीप के पास गए तो वह गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी देने लगा और रुपये वापस करने से इन्कार कर दिया। पुलिस मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करके अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

मैनपाट के सपनादर में तेज रफ्तार कार पेड़ से भिड़ी, 8 घायल

फलदान कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, दरिमा स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिले चिकित्सक

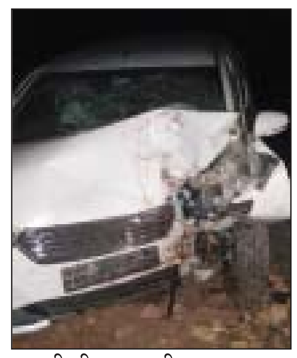

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मैनपाट के सपनादर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 8 लोग घायल हो गए। सभी फलदान कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। नजदीकी अस्पताल में चिकित्सक के नहीं मिलने पर सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रवाना किया गया।

जानकारी के अनुसार सपनादर से कार में सवार होकर आठ लोग दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ा दमाली फलदान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सपनादर के पास वाहन तेज गति में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की खबर मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को नजदीकी शासकीय अस्पताल भेजा, लेकिन दरिमा स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक नहीं मिले, जिससे जिले में लचर चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर सामने आई। अस्पताल में केवल दो नर्सें मौजूद थीं, जिन्होंने डॉक्टर के नहीं रहने के कारण इन्हें भर्ती करने से इन्कार कर दिया। ऐसे में घायलों को आननफानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल रवाना किया गया, यहां मनिजर यादव (25), रामभजन (18), तुलेश्वर (27), पप्पू (18), जितेंद्र (28), प्रेमनाथ (30), करण यादव (19) और अनिल यादव (25) का उपचार चल रहा है।

पुलिस लाइन खेल मैदान पर निर्माण का विरोध, आईजी को सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के पुलिस लाइन मैदान में शहर के नागरिकों और खेलप्रेमियों ने मैदान में प्रस्तावित निर्माण कार्य का विरोध करते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मांग की गई है कि बच्चों और युवाओं के लिए एकमात्र सुरक्षित खेल मैदान को संरक्षित रखा जाए और निर्माण कार्य किसी अन्य स्थान पर किया जाए।

शहर के मध्य में स्थित पुलिस लाइन खेल मैदान वर्षों से बच्चों और युवाओं के लिए खेल एवं शारीरिक अभ्यास का प्रमुख केंद्र रहा है। पुलिस विभाग द्वारा यहां निर्माण कार्य कराने की तैयारी की जा रही है, इससे खेल प्रेमियों में नाराजगी देखी जा रही है। आम नागरिकों का कहना है कि शहर में पहले ही खुले खेल मैदानों की भारी कमी है, यदि यह मैदान भी समाप्त हो गया तो बच्चों को आउटडोर खेलों से वंचित होना पड़ेगा। इसे देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी से मांग की गई है कि पुलिस विभाग अपना निर्माण कार्य किसी अन्य रिक्त भूमि या स्थान पर करें ताकि यह मैदान सुरक्षित रहे। उम्मीद जताई गई है कि पुलिस प्रशासन सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्संबंध में सकारात्मक निर्णय लेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान रजनीश सिंह, पिंकू पाण्डेय, अभिषेक तिवारी, अंशु सिंह, सौरभ मिश्रा, दुर्गेश सिंह, आशीष सिंह, आरूषि, रोहन जायसवाल, विक्रांत, शशांक तिवारी सहित अन्य उपस्थित थे।

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के रामचंद्रपुर क्षेत्र में बालक छात्रावास की शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान राजस्व अमले पर हमला व शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है

जानकारी के अनुसार प्रकरण 9 दिसंबर 2025 का है, जब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों की टीम पुलिस बल के साथ बालक छात्रावास रामचंद्रपुर की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज की तथा लाठी-डंडे से हमला कर शासकीय कार्य में गंभीर व्यवधान उत्पन्न किया। आरोपियों ने करीब दो घंटे तक अधिकारियों को घेरकर रखा और सड़क जाम कर कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगाड़ दी। थाना रामचंद्रपुर में मामले में धारा 296, 351(3), 191(1), 221 एवं 132 बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। तहसीलदार रामचंद्रपुर अश्वनी चंद्रा द्वारा लिखित आवेदन देकर थाना रामचंद्रपुर में अपराध दर्ज करया गया था, और पुलिस ने विवेचना कार्रवाई प्रारंभ की थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। लगातार तलाश और मुखबिर से मिली ठोस सूचना के आधार पर रामचंद्रपुर पुलिस टीम ने सभी फरार आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी

सबर हुसैन पिता स्व हरीश हुसैन 45 वर्ष, जमरूददीन अंसारी पिता स्व. अलाउददीन 42 वर्ष, गददा हुसैन पिता स्व. अलाददीन 24 वर्ष, फिदा हुसैन पिता स्व. हदीश हुसैन 38 वर्ष, शमसेर अंसारी पिता खूदा बख्श 22 वर्ष, मोनिश रजा पिता अकबर अंसारी 19 वर्ष, सभी निवासी रामचन्द्रपुर, इनताज अली पिता हसबुददीन जुलाहा 34 वर्ष निवासी ग्राम रेवतीपुर, अहमद 30 वर्ष, मकसूद आलम पिता महजूदीन उम्र 26 वर्ष दोनों निवासी अनिरूद्धपुर, अरशद एजाज पिता तुफैल अहमद, मुजाहिद हुसैन पिता वकील 34 वर्ष, गुलाम बजदानी पिता गुलाम जिलानी 25 वर्ष, शेरू मंसूरी पिता तसलीम मंसूरी 24 वर्ष निवासी ग्राम रामचंद्रपुर, मोसबार अंसारी पिता आबिद अंसारी 37 वर्ष, आलम अंसारी पिता स्व. अलाउददीन 55 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कलिकापुर, सभी थाना रामचन्द्रपुर व इंतखाब अंसारी पिता मुस्ताक 32 वर्ष निवासी महाबीरगंज विजयनगर थाना रामानुजगंज।

चुनाव में 3 साल शेष, इधर रामानुजगंज की राजनीति में आई गर्माहट

पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की सक्रियता से मची हलचल

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर-रामानुजगंज। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी लगभग तीन वर्ष का समय शेष है, लेकिन रामानुजगंज विधानसभा की सियासत में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह क्षेत्र के चर्चित नेता एवं पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की राजनीतिक सक्रियता मानी जा रही है, जो करीब दो वर्षों की खामोशी के बाद एक बार फिर खुले तौर पर मैदान में नजर आने लगे हैं। उल्लेखनीय है बृहस्पति सिंह को कांग्रेस पार्टी द्वारा लगभग छह वर्षों के लिए पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में निष्कासित किया गया था, इसके बाद वे लंबे समय तक राजनीतिक रूप से शांत नजर आए। हालांकि अब उनकी हालिया गतिविधियों ने रामानुजगंज की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे दिया है। बीते कुछ दिनों से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में दर्शन-पूजन करते हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही वे आम लोगों से भेंट-मुलाकात करके क्षेत्र की समस्याएं सुन रहे हैं। मुलाकातों के दौरान जगह-जगह उनके समर्थक नजर आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि उनकी सक्रियता सुनियोजित है। गौरतलब है कि बृहस्पति सिंह द्वारा अलग राजनीतिक पार्टी बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर भी बयान दिया जा चुका है, उनकी कांग्रेस में वापसी होगी कि नहीं इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस प्रकार से पूर्व विधायक अचानक सक्रिय हुए हैं, उससे यह साफ है कि वे आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। इससे न केवल कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल बढ़ी है, बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल, बृहस्पति सिंह की यह सक्रियता रामानुजगंज विधानसभा की राजनीति में नई ऊर्जा और चर्चा का विषय बन चुकी है। चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन सियासी चालें अभी से शुरू हो चुकी हैं, जिसने क्षेत्र की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। वहीं सोमवार को बृहस्पति सिंह का प्रोटोकॉल जारी हुआ, इसके तहत 36 स्थान पर जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसमें मंदिर और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के निवास पर विशेष तौर पर यह कार्यक्रम रखा गया था। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोटोकॉल के तहत बृहस्पति सिंह मैदान में नजर आए, उनके साथ भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ी भाषा केवल एक संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर

शासकीय कार्यालयों म छत्तीसगढ़ी एवं स्थानीय भाषा प्रयोग करने पर दिया जोर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रशासनिक कार्य व्यवहार म छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग विषय पर आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अपर कलेक्टरी अमृत लाल ध्रुव, विनय सोनी, राजभाषा आयोग की सचिव डॉ. अभिलाषा बेहार, वक्ता डॉ. चितरंजन कर और एडिशनल सीईओ नेहा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। जिले के सभी विभाग प्रमुखों और अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

राजभाषा आयोग की सचिव डॉ. अभिलाषा बेहार ने छत्तीसगढ़ी भाषा के गौरवशाली इतिहास और उसके प्रशासनिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा केवल एक संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे संरक्षित करना और प्रशासनिक कार्यों में लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा 'लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी' नामक एक मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में हिंदी के 67 शब्दों और वाक्यों का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, नोटशीट, छुट्टी आवेदन, और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के प्रारूप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और इसे शासन-प्रशासन में अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है। राजभाषा आयोग ने इस पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा को शासन का हिस्सा बनाने और इसे आम जनता के साथ संवाद का माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

डॉ. चितरंजन कर ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने और इसके विकास के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था और छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के रूप में स्थापित करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का हिस्सा है। डॉ. कर ने बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा लोकोक्ति, अहाना, मुहावरे भावों और शब्दों से वृहद और संपन्न है। छत्तीसगढ़ी भाषा का अपना वृहद शब्दकोष है। छत्तीसगढ़ी की यह विशेषता है कि इसमें क्रिया रूप में स्त्रीलिंग और पुर्लिंग एक ही है। इसमें बहुवचन बनाने के लिए एक ही प्रत्यय है। छत्तीसगढ़ में 36 भाषाएं बोली जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग प्रदेश की भाषाओं को संग्रहित करने का काम कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को हिंदी का सहोदरा बताया। डॉ. कर ने अधिकारी-कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्यादा से ज्यादा कार्यालयीन उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। अंत में उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग को अपनी दिनचर्या एवं प्रशासनिक कार्यों में बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत आज 260 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत 10 फरवरी को शहर के पी.जी. कॉलेज के हॉकी स्टेडियम मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में जिले भर के 260 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रात: 11.30 बजे वर्चुअल रूप से जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे।

वैवाहिक कार्यक्रम प्रात: 09 बजे से आयोजित होगा। इस अवसर पर पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता सांसद सरगुजा चिंतामणी महाराज करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा क्षेत्र लुण्ड्रा के विधायक प्रबोध मिंज, विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो, राज्य गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर की महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह, सभापति नगर पालिक निगम हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव एवं सभापति स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति राधा रवि शामिल होंगे।

मदनपुर में चिन्हांकित गैस गोदाम स्थल के कब्जा को प्रशासन ने हटाया

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत मदनपुर व पण्डोनगर के मध्य प्रस्तावित गैस गोदाम परियोजना हेतु चिन्हित स्थल से तीनों कब्जा धारियों को आज बेदखल कर दिया गया है। कार्यवाही पर स्थानीय लोगों द्वारा अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई गई लेकिन उन्हें हटा दिया गया। दर असल सिलफिली महाविद्यालय के बगल में भारत पेट्रोलियम की गैस गोदाम बनाने की तैयारी लंबे समय से चल रही है। राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में भूमि के नापजोख की प्रक्रिया जब किए जाने का प्रयास किया गया था, तब भी ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे।

गौरतलब है कि सोमवार को लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पैकरा, एसडीओपी अभिषेक पैकरा, जयनगर थाना प्रभारी टीआई रूपेश कुंतल एक्का दलबल के साथ प्रस्तावित गैस गोदाम के चिन्हित स्थल पहुंच गए थे। इसके बाद यहां पर भारी पुलिस बल की उपस्थिति में 40-50 वर्षों से काबिज प्रदीप मंडल, अन्नू पण्डो, स्व. कल्पना राय पति विष्णु राय के कब्जा को हटवाकर यहां पोल गाडकर फेसिंग कार्य पूर्ण कराकर प्रशासन ने उक्त भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत मदनपुर व पण्डोनगर के मध्य एनएच 43 किनारे संचालित शासकीय महाविद्यालय सिलफिली के बाजू में स्थित खसरा नंबर 142, 143, 144, 145, 147 कुल रकबा 1.00 हेक्टेयर भूमि को भारत पेट्रोलियम के गैस गोदाम निर्माण हेतु स्थल चिन्हांकन की प्रक्रिया गत दिनों पूर्ण की गई थी। प्रस्तावित गोदाम स्थल के समीप ही सिलफिली महाविद्यालय के अलावा पार्वती बीएड कॉलेज और कई सरकारी व निजी स्कूल स्थित हैं। प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं यहां अध्ययन के लिए आते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहां सरगुजा संभाग के पांचों जिला हेतु गैस सिलेंडर का भंडारण केंद्र स्थापित हुआ तो किसी भी समय छोटी सी चूक एक भयावह हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे पढ़ाई के लिए कॉलेज और स्कूल जाते हैं, वहां उनके सिर पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। लोगों का मानना है कि गैस गोदाम के आसपास हमेशा रिसाव, आगजनी और धमाके जैसी दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। यदि ऐसी कोई घटना घटित हुई तो न सिर्फ संपत्ति का नुकसान होगा, बल्कि दर्जनों जिंदगियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके और शैक्षणिक संस्थानों के बीच ऐसा प्रोजेक्ट पूरी तरह असुरक्षित है। लोगों का कहना है कि सरकार चाहती है तो गोदाम गांव से दूर, सुनसान जगह पर बनाए। पूरा गांव इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लामबंद हो चुका है।

मोहरा एनीकट में डूबे दोनों किशोर का शव दूसरे दिन बरामद

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत रामनगर में स्थित मोहरा एनीकट पर रविवार दोपहर करीब दो बजे पांच किशोर घूमने पहुंचे थे। वे एनीकट के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी दो किशोरों ने पानी में उतरकर नहाने का फैसला कर लिया। नहाने के दौरान जयनगर कुंजनगर निवासी मो. जावेद का 14 वर्षीय पुत्र अयान सद्दाम और नगर पंचायत शिवनंदनपुर गंवटियापारा में अपने ननिहाल आए सेराज अंसारी के 12 वर्षीय पुत्र आदिन गहरे पानी की ओर चले गए। पानी की गहराई का अंदाजा न होने और तैराकी का अनुभव न होने के कारण दोनों डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों को डूबता देखकर अन्य बच्चों ने शोर मचाया और आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। इस दौरान अयान के बड़े भाई आवेश ने तत्काल दोनों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी की अधिक गहराई के कारण सफलता नहीं मिली। मामले में सोमवार की सुबह काफी मशक्कत उपरांत दोनों किशोरों के शव को बरामद कर पुलिस ने पंचनामा पीएम उपरांत शव परिजन के सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि अयान सद्दाम दोपहर में परिवार के साथ भोजन करने उपरांत बड़े भाई आवेश के साथ बाल कटवाने की बात कहकर घर से निकला था। घरवालों को यह उम्मीद थी कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह दोस्तों के साथ मोहरा एनीकट पहुंच जाएगा। वहीं आदिन भी घर से दोस्तों के साथ खेलने की बात कहकर निकला था। ज्ञात हो कि दोनों किशोरों के शव मिलने उपरांत क्षेत्र में शोक का माहौल निर्मित हो गया है। बताया जा रहा है कि सेराज अंसारी के 12 वर्षीय पुत्र आदिन मनेंद्रगढ़ में रहकर पढ़ाई करता था, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी अब दो बहन ही रह गई हैं।

ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। बाइक में पेट्रोल भरवाकर एनएच 43 पर पहुंचे बाइक सवार ट्रक के पिछले चक्का की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नयनपुर खुटरापारा निवासी करीब 25 वर्षीय गोविंद राजवाड़े सोमवार की दोपहर में अपनी बाइक क्रमांक सीजी 15 डीएल 1711 में ग्राम पंचायत तेलईकछार शशिपुर में स्थित एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल वाहन में भरवाकर जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर पहुंचा तभी ट्रक क्रमांक 15 ए 9646 की चपेट में आ गया। दुर्घटना में युवक के पैर में गंभीर चोट आई है। जिसे जयनगर पुलिस मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवा दिया गया है।

सुरक्षित आवास के लिए मुन्नी ने जताया आभार

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासन-प्रशासन के सतत् प्रयासों से जिले के पहाड़ी कोरवा जनजातीय परिवारों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिसके अंतर्गत पीएम जनमन आवास योजना से मुन्नी बाई पहाड़ी कोरवा आवास से लाभान्वित हुई है।
जिले के विकासखंड राजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत घटगांव निवासी श्रीमती मुन्नी बाई पहाड़ी कोरवा को आवास का लाभ मिला है। श्रीमती मुन्नी बताती है कि शासन द्वारा पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत राशि सीधे उनके बैंक खाते में आबंटित की गई।

राशि प्राप्त होने के पश्चात हितग्राही श्रीमती मुन्नी बाई द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया और आज वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित आवास में जीवन यापन कर रही हैं। वे कहती है कि पहले बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। पैसे के अभाव में घर की मरम्मत भी नहीं करा पा रही थी, लेकिन पीएम जनमन योजना ने उनके आवास के सपने को साकार किया है और अब आवास मिलने से काफी सहूलियत हुई है। श्रीमती मुन्नी कहती है कि योजना से कई निम्न वर्गीय परिवारों को पक्का मकान का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने योजना के लिए शासन और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सामूहिक कन्या विवाह का भव्य आयोजन आज, 150 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विवाह समारोह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में प्रात: 09 बजे से प्रारंभ होगा। जहां 150 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेगें।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय वर्चुअल माध्यम से जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देगें। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में आदिम जाति विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशु पालन मंत्री श्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सामरी विधायक श्रीमती उधेश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंहदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेरवा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री लोधीराम एक्का शामिल होंगे।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार का शुभारंभ

अपने बच्चों के पोषण स्तर का मापन अवश्य कराने अभिभावकों से की गई अपील

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सही तरीके से वजन एवं ऊंचाई मापन किया जा रहा है, ताकि उनके पोषण स्तर का सटीक आकलन किया जा सके। वजन त्यौहार के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित बच्चों का निर्धारित मानकों के अनुसार वजन व लंबाई मापी गई। साथ ही माताओं एवं किशोरियों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार, उसके महत्व तथा बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में पोषण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वजन त्यौहार के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग द्वारा दीवार लेखन के माध्यम से जन-जागरूकता लाई गई। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गृह भेंट कर अभिभावकों को वजन त्यौहार की जानकारी दी गई और बच्चों को केन्द्रों में लाने हेतु प्रेरित किया गया। वजन त्यौहार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी परियोजना कार्यालय में परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परियोजना स्तरीय वजन त्यौहार प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, ताकि मापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। प्रशिक्षण के दौरान सही विधि से वजन एवं ऊंचाई मापन, अभिलेख संधारण तथा आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर अपने बच्चों के पोषण स्तर का मापन अवश्य कराएं, ताकि समय रहते कुपोषण की पहचान कर उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
गौरतलब है कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रो में पोषण व स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित किया जा रहा है। साथ ही 09 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार मनाया जाएगा।

प्रशासन की सजगता से रुकवाया गया बाल विवाह

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर नियंत्रण के लिए जिले में जिला प्रशासन द्वारा सतत एवं सजग प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुर में प्रशासन की तत्परता और समन्वित प्रयास से 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। जिससे बालिका का भविष्य सुरक्षित हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सोनपुर में एक नाबालिग बालिका का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन बलरामपुर तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थल पर पहुंचकर जांच की जिसमें बालिका की आयु 15 वर्ष पाई गई। टीम ने मौके पर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,

2006 के प्रावधानों की जानकारी दी तथा परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में समझाइश दी गई। इससे बालिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अल्प आयु में मातृत्व से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। समझाइश पर परिजनों ने बालिका की सही आयु में विवाह करने की बात कही। इस दौरान ग्रामवासियों से भी अपील की गई कि वे अपने आसपास इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम सभाओं एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानून की जानकारी दी जा रही है। साथ ही समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सूरजपुर जिला न्यायालय भवन निर्माण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की शेष राशि स्वीकृत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले में बहुप्रतीक्षित जिला न्यायालय भवन निर्माण को लेकर एक अहम प्रशासनिक कदम सामने आया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जिला न्यायालय भवन के लिए आवंटित भूमि में शामिल राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन से जुड़ी शेष राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे अब न्यायालय भवन निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुरजपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने बताया कि सूरजपुर जिला न्यायालय भवन निर्माण हेतु कुल 1.82 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए शेष 14 लाख 85 हजार रुपए की स्वीकृति विधि विभाग नवा रायपुर द्वारा प्रदान की गई है। इस संबंध में उच्च न्यायालय बिलासपुर के एडिशनल रजिस्ट्रार प्रशासन संतोष ठाकुर द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर को औपचारिक ज्ञापन जारी किया गया है। ज्ञापन में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त स्वीकृत राशि को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), संभाग सूरजपुर के माध्यम से वनमंडलाधिकारी, वनमंडल सूरजपुर के कैंपा खाते में शीघ्र जमा कराया जाए। राशि जमा होने के पश्चात संबंधित वन भूमि का विधिवत आवंटन कर उसे न्यायालय प्रशासन के पूर्ण आधिपत्य में लिया जाएगा। साथ ही भूमि का कब्जा प्राप्त होने के बाद उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को इसकी सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब यह प्रक्रिया पूरी होते ही वर्षों से लंबित सूरजपुर जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो जाएगा। शर्मा ने बताया कि नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण से न्यायिक कार्यों में सुविधा बढ़ेगी, अधिवक्ताओं और वादकारियों को बेहतर आधारभूत संरचना मिलेगी तथा न्यायिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। लंबे समय से लंबित इस परियोजना को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर तेजी दिखाई दे रही है, जिससे आमजन में भी सकारात्मक संदेश गया है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा शुल्कों में किए वृद्धि पर एनएसयूआई ने जताया एतराज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। एनएसयूआई के पूर्व जिला संयोजक अविनाश साहू ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के शुल्कों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा पर डकैती कर रही है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या अब प्रदेश में गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा। पूर्व जिला संयोजक अविनाश साहू ने बताया कि शिक्षा मंडल ने फीस में जो वृद्धि की है वह बेहद चौंकाने वाली है। साहू ने बताया कि नियमित परीक्षा शुल्क जो पहले 460 रुपए था, उसे बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। नामांकन शुल्क भी 80 रुपए की जगह अब छात्रों को 200 रुपए देने होंगे। विलंब

शुल्क भी 1540 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। साहू ने कहा सूरजपुर जिला आदिवासी बाहुल्य और किसान प्रधान जिला है। यहां के अभिभावक बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक तरफ भाजपा सरकार मुफ्त शिक्षा की बात कहती है और दूसरी तरफ परीक्षा फॉर्म के नाम पर मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों की जेब काट रही है। सरकार अपना बजट घटा कर छात्रों की फीस से खजाना भरना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्रों पर डाले गए इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ का औचित्य क्या है। अगर सरकार ने इस जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लिया, तो एनएसयूआई घर-घर जाकर सरकार के इस शिक्षा विरोधी चेहरे को उजागर करेगी और छात्रों के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से आवाज उठाएगी।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 11 फरवरी को

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 11 फरवरी 2026 को 11 बजे संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा एवं विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।

केंद्रीय बजट 2026-27 दीर्घकालीन विकास का रोडमैप : अनुराग सिंहदेव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

एमसीबी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने केंद्रीय बजट 2026-27 को दीर्घकालीन विकास का रोडमैप बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देने वाला है। जनपद सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बजट रिफार्म ओवर रिहोरट्रिक के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य देश की संभावनाओं को प्रदर्शन में बदलना है, उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन प्रमुख कर्तव्य तय किए हैं उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर तेज आर्थिक विकास, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें समृद्धि का सहभागी बनाना तथा सबका साथ-सबका विकास के विजन को साकार करना। उन्होंने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये के स्मूश्व ग्रोथ फंड और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के टॉप-अप से छोटे और मध्यम उद्योगों को इम्टी सपोर्ट मिलेगा, कॉपोर्रेट मित्रास पहल से टियर-2 और टियर-3 शहरों में व्यवसायिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। श्री सिंहदेव ने बताया कि बजट में फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। यह वित्तीय अनुशासन विकास को गति देने के साथ-साथ कर्ज नियंत्रण में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज संतुलित खर्च और तेज आर्थिक प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि 12.2 लाख करोड़ रुपये के पब्लिक कैपेक्स से सड़क, रेल, एयरपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश से भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से हाई-वैल्यू इंजीनियरिंग और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,राष्ट्रीय जलमार्ग विस्तार और सी-प्लेन कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। वहीं शिक्षा, स्किल और सर्विस सेक्टर को जोड़कर 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज में भारत की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है,मेडिकल टूरिज्म, एनीमेशन, गेमिंग और यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसी योजनाओं से युवाओं को भविष्य के रोजगार से जोड़ा जाएगा। फसल विविधीकरण, मत्स्य पालन विकास और ग्रामीण उद्यमिता से किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है, सामाजिक समावेशन के तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर विस्तार का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे नियम सरल होंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। आईटी सर्विसेज और डेटा सेंटर सेक्टर को दिए गए प्रोत्साहन भारत को वैश्विक डिजिटल हब बनाने में मदद करेंगे।

पीएम आवास नहीं बनाए तो वापस करनी होगी राशि, एसडीएम ने दी समझाईस

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पीएम आवास ग्रामीण अंतर्गत राज्य शासन एवं कलेक्टर एस.जयवर्धन व सीईओ जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन हो रही है। राज्य स्तर पर विगत 10 माह में 5 लाख से अधिक आवास निर्मित हुए है एवं जिले से 18 हजार से अधिक आवास पूर्ण हुए है। शासन स्तर से पूर्णता के लिए शेष बचे हितग्राहियों के आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त परिपालन में अधिकतर हितग्राही कार्य को गति दे रहे है। किंतु कुछ ऐसे भी हितग्राही है जो आवास निर्माण के लिए राशि लेकर कार्य नहीं करा रहे है। इन्हें बार बार समझाइस एवं नोटिस देने के उपरांत अंततः एसडीएम के समक्ष प्रशि कराई जा रही है। एसडीएम रामानुजनगर अजय मोडियम के द्वारा आवास निर्माण के लिए दिए गए

संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान पर जोर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा की अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी यादव जिले के प्रवास पर रहीं एवं उनका गरिमामय उपस्थिति बैठक में रहीं। बैठक संघ के जिलाध्यक्ष के आवास पर आहुत किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अयोध्या में संपन्न हुई त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन की उपलब्धियों तथा पेंशनरों के हित में लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में विस्तार से बताते हुए संघ की सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री ने भी अपना विचार रखा और संगठन को मजबूत करने का आहवान किया। प्रदेश सचिव ने कहा कि संघ का विस्तार

जिला एवं संभाग के विकास खंड स्तर पर करने हेतु सभी प्रयासरत हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के आगमन पूर्व राम रतन पटेल, अनिल कुमार तिवारी, महिला बाल विकास विभाग से श्रीमती चिंतामणि सिन्हा, श्रीमती सरिता सिंह ने संघ की आजीवन सदस्यता ग्रहण किए। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, प्रदेश सचिव प्रदीप सोनी सहित संभागीय अध्यक्ष गुरचरण सिंह, जिलाध्यक्ष मानिक चंद, भगवान चरण अग्रवाल, पी.सी. मेहता आदि उपस्थित रहे।

केंद्रीय बजट विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर - अखिलेश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। केंद्रीय बजट 2026 किसान, युवा, महिला, व्यापारी एवं मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने यहां जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहीं। प्रदेश महामंत्री श्री सोनी ने कहा कि यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा देश को तकनीकी रूप से सशक्त करने वाला है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल, सड़क, रक्षा एवं पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि

की गई है। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए पांच नई विश्वविद्यालय नगरी स्थापित की जाएंगी। चलचित्र निर्माण, दृश्य प्रभाव, खेल निर्माण एवं चित्रकथा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 20 लाख प्रशिक्षित पेशेवर तैयार किए जाएंगे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 10 हजार युवाओं को पर्यटन मार्गदर्शक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। महिलाओं के लिए बजट में स्व-सहायता उद्यमी बाजार की घोषणा की गई है। लखपति दीदी योजना का विस्तार करते हुए अब इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ महिलाओं तक किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 28,183 करोड़ रुपये किया गया है। किसानों के हित में पशुपालकों के लिए ऋण अनुदान, मछली पालन हेतु 500 बड़े तालाबों का निर्माण, अखरोट एवं बादाम उत्पादक किसानों के लिए विशेष योजनाएं तथा छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। श्री सोनी ने बताया कि कर सुधारों के अंतर्गत विदेश यात्रा पर लगने वाले स्त्रोत पर कर संग्रह की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। प्रवासी भारतीयों को संपत्ति विक्रय हेतु अब अलग पहचान संख्या की आवश्यकता नहीं होगी तथा आयकर विवरणी भरने की तिथि भी बढ़ाई गई है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन और वर्तमान केंद्र सरकार की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, किसान, रेल एवं पूंजीगत व्यय का बजट सीमित था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि हुई है।

छत्तीसगढ़ को विशेष लाभ

प्रदेश महामंत्री ने बताया कि बजट में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं केरल के लिए खनन गलियारे के विकास की घोषणा की गई है, जिससे खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रेल बजट में भी छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देते हुए 7,470 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, जिला महामंत्री शशिकांत गर्ग, जिला उपाध्यक्ष संत सिंह, जिला कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, धर्मवीर, पवन साहू, नीरज गुप्ता, संदीप साहू, जितेंद्र शर्मा, सचिन तायल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

14 मार्च को आयोजित वर्ष के पहले नेशनल लोक अदालत हेतु हुई बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वाधान में, वर्ष 2026 के प्रथम नेशनल लोक अदालत 14 मार्च के सफल एवं प्रभावी आयोजन हेतु महत्वपूर्ण तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों एवं समस्त बैंक प्रबंधकों के साथ गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती विनीता वार्नर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मानवेन्द्र सिंह, जिला एवं अपर

सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, आनंद प्रकाश वारियाल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुश्री पायल टोपनो, नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग के अधिकारीगण तथा जिले में संचालित समस्त बैंक प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि 14 मार्च को वर्ष का यह पहला नेशनल लोक अदालत आयोजित होने जा रहा है। उन्होने नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग के अधिकारीगण तथा जिले में संचालित समस्त बैंक प्रबंधकों को लंबित प्रकरणों, प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित कर अविलम्ब प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए एवं ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निवारण हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करने पर जोर दिया। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने हेतु गहन चर्चा की गई कि संबंधित विभागों द्वारा बकाया राशि, ब्याज और जुमार्ने पर वास्तविक एवं प्रभावी छुट प्रदान किये जाए, ताकि जनता को अधिकतम वैधानिक राहत मिल सके। जिले वासियों से अपील की गई कि 14 मार्च के नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं। लोक अदालत का आयोजन जिले के सभी न्यायिक क्षेत्राधिकारों में किया जाएगा, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं जिले के समस्त अनुविभागीय और तहसील न्यायालय शामिल हैं।

बिना निर्माण किए निकाल लिए लाखों रुपए, शिकायत के बाद भी नहीं हुई जांच

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनपुर। सरगुजा जिले के आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में पंचायत में निर्माण कार्य कराए बिना ही पूर्व सरपंच-सचिव के द्वारा लाखों रुपए गबन किए जाने का मामला सामने आया है। सरपंच और ग्राम वासियों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जनपद सीईओ सहित सरगुजा के कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग की गई थी। कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो निर्माण कार्यों की जांच हुई और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल पुरा मामला

लखनपुर और मैनपाट विकासखंड के सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत डांड केसरा का है। जहां के सरपंच अजीत सवता और ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत डांड केसरा मे सीसी सड़क निर्माण, ढोडी निर्माण ,नाली निर्माण, घाट कटिंग, कुआ निर्माण, संहित अन्य निर्माण कार्य पंचायत में किए बिना ही पूर्व सरपंच-सचिव राम गोपाल साहू के द्वारा लाखों रुपए गबन कर लिया गया है। सरपंच अजीत सवता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 2025 में निर्माण कार्य किए बिना ही राशि गवन किए जाने की शिकायत जनपद के तत्कालीन सीइओ वेद प्रकाश पांडे एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को की थी।

महिला और बच्चों की परेशानी को देखते हुए आंगनबाड़ी खोले जाने की मांग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनपुर। सरगुजा जिले के मैनपाट लखनपुर विकासखंड के सीमा पर स्थित ग्राम डांड केसरा घुई डांड पारा में आंगनबाड़ी नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा घुई डांड पारा में आंगनबाड़ी खोले जाने की मांग की जा रही है। घुई डांड पारा में लगभग दो दर्जन से अधिक परिवार निवासरत है और प्रत्येक घरों में दो से तीन बच्चे हैं, आंगनबाड़ी नहीं होने से इन्हें 2 किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी जाने पड़ता है। जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मांग पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु सुकृति मिली। जिसका निर्माण विगत 7 वर्षों पूर्व ग्राम पंचायत के द्वारा प्रारंभ कर फाउंडेशन की

खुदाई की गई, पर निर्माण एजेंसी के द्वारा कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया। लगभग 110000 रुपए राशि भी आहरण कर लिया गया। जिसे लेकर ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई और शिकायत के बाद हुई जांच में निर्माण एजेंसी पर लगभग 110000 रुपए राशि की वसूली हेतु नोटिस भी जारी किया गया था। आंगनवाड़ी भवन नहीं बनने से आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मांग की है जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ यहां के निवासियों को मिल सके।

इस संबंध में परियोजना अधिकारी असीम शुक्ला से बात करने पर उनके द्वारा कहा गया कि मौका जांच करने उपरांत उच्च अधिकारियों को संबंध में अवगत कराया जाएगा और ग्राम सभा का प्रस्ताव मंगवाकर आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने हेतु पहल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

मंडल युवा मोर्चा को मिला नया नेतृत्व, ज्ञान प्रकाश दुबे बने अध्यक्ष

भटगांव। मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ज्ञान प्रकाश दुबे को सौंपे जाने से भटगांव मंडल में उत्साह का माहौल देखा गया। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ज्ञान प्रकाश दुबे ने शीर्ष नेतृत्व, जिला संगठन एवं समस्त सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास और जिम्मेदारी सौंपी है, उसका वे पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से निर्वहन करेंगे। ज्ञान प्रकाश दुबे इससे पूर्व भटगांव मंडल युवा मोर्चा के महामंत्री, युवा मोर्चा मंडल कार्यसमिति सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उसके पुर्व ज्ञान प्रकाश दुबे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं तथा वे धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। संगठन के प्रति उनकी निरंतर मेहनत, समर्पण और संघर्ष को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने भाजपा की विचारधारा को मजबूती से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है।

देवीपुर जागरूकता शिविर में न्यायधीश ने कानून की बारीकियों से कराया अवगत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत देवीपुर में वृहद कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, आनंद प्रकाश वारियाल ने की। उन्होने उपस्थितो को सरल भाषा में कानून की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा हम अपने बच्चों को मोबाईल उपलब्ध करा देते है, किन्तु बच्चा मोबाईल में क्या-क्या करता है इसपर कोई ध्यान नही देता। उन्होने उपस्थित सभी ग्रामीणजन से पॉक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट के

मामलों के उदाहरण पेश किये और अपील करते हुए कहा हर माता-पिता को अपने बच्चे की मोबाईल एक्टिविटी को चेक करते रहना चाहिए। बालपन में बच्चों का मन अक्सर बुरी चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। आगे उन्होने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों को बताते हुए कहा आप अपने आपको कभी कमजोर न समझे न्याय कि लडाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर कदम आप के साथ खडा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान उपलब्ध कराती है किसी प्रकार की सहायता या सलाह के लिए नालसा के 15100 एवं नालसा की वेबसाईट पर जाकर या सीधे जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। 14 मार्च को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए लोक अदालत के फायदे गिनाए साथ ही मध्यस्थता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की मध्यस्थता एक स्वैच्छिक और गोपनीय प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष विवादित पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने में मदद करता है। यह अदालत के बाहर विवाद सुलझाने का एक प्रभावी, त्वरित और गोपनीय तरीका है जो आपसी संबंधों को बचाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने मोटर व्हीकल एक्ट, बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम, आबकारी अधिनियम, टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं कैरियर गाईडेंस की पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। न्यायाधीश के द्वारा प्रदान की गई जानकारीयों से लोग इतने प्रभावित हुए और प्रश्नोत्तरी समय पर कई सवाल पुछे जिनका न्यायाधीश ने बडे ही सलता से जवाब दिया।

भारत और अमेरिका के मध्य दीर्घकाल से जारी बातचीत के तत्पश्चात व्यापार समझौते को लेकर एक सकारात्मक सहमति बन गई है। व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामान पर आयाद किया गया 50 फीसदी टैरिफ घटाकर मात्र 18 फीसदी कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ घटने से भारतीय बाजार में उत्साह है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल आयात बंद करने के लिए दबाव बनाया है। हालांकि, अभी तक इस बारे में मोदी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। वहीं, कृषि फसलों को लेकर देश का किसान वर्ग चिंतित है। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अमेरिकी के साथ यह ट्रेड डील भारत के लिए लाभदायक होगी या नहीं, इसी का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के मायने

विश्लेषण
प्रभात कुमार राय
विदेशी मामलों के जानकार

राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया है कि यदि भारत द्वारा पूर्णरूपेण रूस से तेल का आयात रोका नहीं किया गया तो फिर अमेरिका-भारत व्यापार समझौता रद्द कर दिया जाएगा। यदि वास्तव में भारत ने रूस से तेल आयात रोक दिया तो मोदी को अपनी शक्तिशाली राजनीतिक छवि बचाना मुश्किल हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अभी अमेरिका में कोई इंवेस्टमेंट करने का कमिटमेंट नहीं किया गया है। यह स्वाभाविक है कि भारत को विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए अधिक प्रोडक्ट खरीदने पड़ सकते हैं।

भारत और अमेरिका के मध्य दीर्घकाल से जारी बातचीत के तत्पश्चात व्यापार समझौते को लेकर एक सकारात्मक सहमति बन गई है। हालांकि अभी तक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का संपूर्ण प्रारूप सामने नहीं आया है। व्यापार समझौते के विषय में केवल राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया गया ऐलान और अमेरिकी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड द्वारा प्रदत्त जानकारी ही उपलब्ध हुई है। मैकलियोड ने फरमाया कि भारत द्वारा रूस से तेल का आयात बंद कर देने के वादे के तत्पश्चात भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से अमेरिका को आयात किए जाने वाले सामान पर आयाद किया गया 50 फीसदी टैरिफ घटाकर मात्र 18 फीसदी कर दिया है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा रूस से तेल का आयात एकदम बंद कर देने के विषय में कोई उद्घोषणा अभी तक नहीं की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया है कि यदि भारत द्वारा पूर्णरूपेण रूस से तेल का आयात रोका नहीं किया गया तो फिर अमेरिका-भारत व्यापार समझौता रद्द कर दिया जाएगा।

रूस से तेल का आयात कम

उधर, रूस सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर भारत ने कोई जानकारी अभी तक प्रदान नहीं की है। उल्लेखनीय है कि भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से पहले ही भारत सरकार द्वारा रूस से तेल का आयात काफी कम कर दिया गया है। विगत कुछ वर्षों से रूस से भारत अपनी आवश्यकता का तकरीबन 50 प्रतिशत तेल आयात करता रहा था, किंतु अब केवल 25 प्रतिशत तेल आयात कर रहा है। रूस से तेल आयात कम कर देने के सवाल पर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार पर अत्यंत आक्रामक है। विपक्ष द्वारा यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया

है। यदि वास्तव में ही भारत ने अमेरिका व्यापार

समझौते के तहत रूस से तेल आयात करना एकदम रोक दिया तो नरेंद्र मोदी को अपनी शक्तिशाली राजनीतिक छवि बचाना मुश्किल हो जाएगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अभी अमेरिका में कोई इंवेस्टमेंट करने का कमिटमेंट नहीं किया गया है। यह स्वाभाविक है कि भारत को विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए अधिक प्रोडक्ट खरीदने पड़ सकते हैं।

भारत के लिए अमेरिका बड़ा बाजार

यक्ष प्रश्न है कि क्या भारत - अमेरिका व्यापार समझौते के तत्पश्चात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्थिति और अधिक शक्तिशाली बन जाएगी अथवा कमजोर पड़ जाएगी। भारत का राजनीतिक विपक्ष इस वक्त जबकि भारत अमेरिका समझौता एक प्रारूप ले चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर बेहद आक्रामक है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका वस्तुतः भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार रहा है। इस व्यापार समझौते के बाद होने वाले परिवर्तनों में छोटे निवेशकों की चिंता बहुत कुछ बढ़ा दी है। इसका कारण यह है कि आने वाले वक्त में भारत से अमेरिका को 800 डॉलर तक के सामान को बिना शुल्क भेजने की

सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। विगत वर्ष 2025 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ युद्ध प्रारंभ किया गया था तो फिर चरणबद्ध तौर तरीकों से भारतीय सामान पर 50 फ़ीसदी तक टैरिफ आयद कर दिया गया था। सर्वविदित है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों में एक विशाल संख्या छोटे उद्योगों के मालिकों और उनमें कार्य करने वाले करोड़ों श्रमिकों की रही है।

रोजगार और आय प्रभावित

अमेरिका को निर्यात करने वाले सामान में आई कमी का सीधा प्रभाव रोजगार और आय पर पड़ता है। अमेरिका की धारा 321 के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा कस्टम प्रक्रिया को भी तेल और सम बनती है जिससे निर्यातक पूरी तरह अनुपालन के साथ व्यापार कर सकते थे इस सुविधा के अभाव में भारतीय निर्यातक यकीनन उन देशों की तुलना में पिछड़ जाएंगे जिन्हें अभी तक ऐसी छूट उपलब्ध है। अमेरिकन टैरिफ आयद होने के बाद हस्तशिल्प और श्रम पर आधारित उत्पाद बनाने वाले छोटे उद्यमी अब अधिक लागत के कारण अमेरिका बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। पहले से मिलने वाली सीमा ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी सुगम बनाती थी। अमेरिकी

ग्राहकों को सीधे भारतीय उत्पाद पहुंचना होता था। अतिरिक्त शुल्क या जटिल दस्तावेज की प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती थी। रूस भारत का दशकों पुराना मित्र रहा है। भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है और महाशक्तियों के मध्य कशमकश के दौर में भारत किसी भी सैन्य गुट में कदाचित शामिल नहीं हुआ। अमेरिका का जबरदस्त दबाव है कि टैरिफ केवल तभी कम किया जाएगा, जबकि भारत रूस से तेल खरीदना एकदम बंद कर देगा।

इस कठिन परीक्षा में यदि भारत वस्तुतः अमेरिका के समक्ष जरा सा भी झुक गया और उसने रूस के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को शिथिल कर दिया तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए अपनी साख बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक विपक्ष को भरपूर मौका मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके और राष्ट्र के हितों को ताक पर रखने का संगीन इल्जाम आयद कर सके। इस राजनीतिक स्थिति को नरेंद्र मोदी की सरकार बाकायदा समझती है। अतः डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर थोपी गई रूस से तेल एकदम नहीं खरीदने की शर्त को कदाचित भी मोदी सरकार स्वीकार नहीं करेगी।

भारत न झुका है और न झुकेगा

डोनाल्ड ट्रंप लैटिन अमेरिकन देश वेनेजुएला के तेल पर आधिपत्य करने के पश्चात यह दावा पेश कर रहे हैं कि उनके पास दुनिया का 70 प्रतिशत तेल है। डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा। एक हद तक भारत ने अमेरिका के कृषि क्षेत्र के लिए अपना मार्केट खोल दिया है। हालांकि मुख्य तौर पर भारत के डेयरी क्षेत्र और मुख्य कृषि उत्पादन के लिए अमेरिकन कृषि उत्पादों के लिए भारतीय मार्केट नहीं खोला गया है। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ भी सम्मानजनक व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। केवल अमेरिका ऐसी अनुचित शर्त भारत पर थोपने की कोशिश कर सकता है कि भारत अमेरिका के कूटनीतिक हुकम का पालन

करे। भारत कभी भविष्य में ऐसा नहीं करेगा।

भारत के हित में है अमेरिकी ट्रेड डील

मुद्दा
अरविंद जयतिलक
वरिष्ठ पत्रकार

महीनों बातचीत के उपरांत आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ घटने से बाजार बम-बम है और कारोबार का पहिया नाच उठा है। दोनों देशों के कारोबारियों के माथे पर जो द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव की शिकन थी, अब वह उत्साह में तब्दील हो चुकी है। आर्थिक संबंधों की नई उर्जा के प्रवाह ने निर्यात के उछाल की उम्मीद जगा दी है। टैरिफ घटने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। भरोसे का संकट खत्म हुआ है और संबंधों के एक नए युग की नींव पड़ गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2025 में 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था और उसके बाद रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25 फीसदी पेनॉल्टी लगाकर टैरिफ को 50 फीसदी कर दिया था। इससे न केवल भारत की मुश्किलें बढ़ी थी, बल्कि अमेरिकी बाजार भी अनिश्चितता की भेंट चढ़ने लगा था। अर्थात टैरिफ बढ़ाने का खामियाजा अमेरिका को ही भुगतने की नौबत आन पड़ी। भारत पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में न सिर्फ महंगाई बढ़ने लगी, बल्कि उसे कम जीडीपी और डॉलर के कमजोर होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया। टैरिफ के सप्लाई-साइड इफेक्ट्स और एक्सचेंज रेट में बदलाव का नकारात्मक असर अमेरिका पर साफ दिखने लगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भारत पर टैरिफ कम करने का दबाव बढ़ गया। स्वागत योग्य है कि ट्रंप ने भारत से 50 फीसदी टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। रूस के साथ तेल व्यापार के चलते लगाया गया अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सकल आंकलन करें तो 32 फीसदी टैरिफ की राहत मिली है। इससे अमेरिका में कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियों की मार्जिन में सुधार होगा और उनकी माली सेहत भी मजबूत होगी। अब भारत को दीर्घकालिक रणनीति के रोडमैप को मूर्त रूप देकर वैश्विक कारोबारी चुनौतियों से पार पाना होगा। यहां अच्छी बात यह है कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत पर अभी भी टैरिफ कम है। अब हम बेहतर उत्पाद और कम टैरिफ के साथ अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह चीन की तुलना में भी टैरिफ कम है। इस कारण चीन से हमें अतिरिक्त डिमांड मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। गौर करें तो अमेरिका ने जिन सेक्टरों पर टैरिफ घटाया है वे हमारे श्रम-उत्पाद निर्यात की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। इन सेक्टरों से हम बड़े पैमाने पर अमेरिका को निर्यात करते हैं। इनमें रेडिमेड गारमेंट, जूलरी, झींगा मछली, हीरे-जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, कीमती पत्थर इत्यादि प्रमुख हैं। गौर करें तो अमेरिकी टैरिफ घटने से सोने-चांदी की जूलरी पर 25 फीसदी, रेडिमेड गारमेंट पर 37 फीसदी, कालीन पर 13.7 फीसदी, बेडशीट पर्दे पर 27 फीसदी और झींगा तथा हीरे पर 7 फीसदी टैरिफ कम हुआ है। इससे इन सेक्टरों के उत्पादों की लागत में कमी आएगी और डिमांड बढ़ेगी। टैरिफ में कमी का सीधा फायदा भारत के उन उद्योगों को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, टैरिफ कम होने से भारतीय उपभोक्ताओं को लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके पार्ट कम कीमत पर उपलब्ध होगा। ट्रेड डील पर संशय के बादल छंटने से अब विदेशी निवेशक भी भारत की ओर रुख तेज करेंगे। विशेष रूप से अमेरिकी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ेगा। ऐसा इसलिए कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध वर्तमान में अपने सबसे मजबूत दौर में है। वर्ष 2000 से वर्ष 2025 के बीच अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक रहा है, जिसमें 70.65 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 132.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अच्छी बात यह है कि भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों मसलन कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। इसे लेकर ढेर सारी आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दो टूक कहा है कि देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों

कारोबारी रिश्ते को नई ऊंचाई मिलेगी और आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दो टूक कहा है कि देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हित सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते को नई ऊंचाई मिलेगी और आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।

रूस से तेल खरीद पर संशय बरकरार

रणनीति
डा. एन. के. सोमानी
वरिष्ठ पत्रकार

भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतिक्षित व्यापार समझौते पर सहमति हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। समझौते के तहत अमेरिका एक कम पारस्परिक वाले टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। जबकि नई दिल्ली अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क घटाकर शून्य कर देगी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात को शून्य करने पर सहमति जताई है। भारत अब रूस की बजाए अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। भारत कृषि जैसे संवेदनशील बाजारों को खोलेगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं खरीदेगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में 18 प्रतिशत टैरिफ किए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया और वैश्विक शांति के लिए उनके प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया। लेकिन मोदी ने ट्रंप की उस घोषणा पर कुछ नहीं कहा जिसमें उन्होंने अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदने, कृषि बाजार खोलने की बात कही है। हालांकि मोदी सरकार ने रूस से तेल की खरीद बंद किए जाने के दावे पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सरकार का कहना है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी आधार पर आयात से जुड़े फैसले किए जाते हैं। ट्रंप की कथित पोस्ट के बाद जो सवाल देश को परेशान कर रहे हैं ,उनमें एक सवाल रूस से तेल खरीद को लेकर भी है। रूस भारत का रणनीतिक सहयोगी और सदाबहार दोस्त है। पिछले लंबे समय से भारत रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। वॉशिंगटन के दबाव में आकर अगर भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह से बंद कर देता है तो इससे नई दिल्ली और मॉस्को के संबंध खराब हो सकते है। जाहिर है कि भारत मॉस्को के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को खराब नहीं करेगा। हालांकि, आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले कुछ माह में भारत की रिफाइनरियों ने रूसी तेल के ऑर्डर में भारी कटौती की है। रिलायंस इंड्रस्टीज ने तो यहां तक कह दिया है कि उसे जनवरी 2026 में रूस से कोई तेल नहीं मिला। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में आयात में लगभग 27 प्रतिशत की कमी आई हैं। नवंबर में यह 3.7 अरब डॉलर था। दिसंबर 2024 के मुकाबले पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में यह 15 प्रतिशत कम है। दिसंबर 2025 में भारत के कुल 11.4 अरब डॉलर के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत रही। अहम बात यह है कि इस अवधि के दौरान अमेरिका से तेल आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। दरअसल, अमेरिकी प्रतिबंधों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच रूस से होने वाला आयात पिछले कई महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा रूस की दिग्गज तेल कंपनियों रोजनेफट और लुकोइल पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध है। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहिए। दरअसल वेनेजुएला की भारत से दूरी काफी ज्यादा है। इससे तेल की लागत हर बैरल पर 374 डॉलर बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब तक वेनेजुएला भारत को तेल खरीद पर बड़ी छूट न दे भारत को फायदा नहीं होगा। ऐसे में अगर भारत ट्रंप की इस मांग को दरकिनार कर देता है तो क्या समझौता मूर्त रूप ले सकेगा यह सवाल भी अहम है। इन तमाम सवालों के जवाब तभी सामने आएंगे, जब व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। हालांकि समझौते को लेकर टंप प्रशासन और मोदी सरकार दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जब तक समझौते का वास्तविक स्वरूप अर्थात ड्राफ्ट सामने नहीं आता, तब तक यह कहना मुश्किल है कि समझौते में बनी सहमति किसके हित सुनिश्चित करती है।

वॉशिंगटन के दबाव में आकर अगर भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह से बंद कर देता है तो इससे नई दिल्ली और मॉस्को के संबंध खराब हो सकते है।

टैरिफ वार छेड़ने वाले ट्रंप आखिर भारत के सामने नतमस्तक हुए

कूटनीति
रवि शंकर
वरिष्ठ पत्रकार

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौता करने की घोषणा की है। इसे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समझौतों में से एक कहा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस समझौते की सबसे बड़ी वजह मौजूदा वैश्विक राजनीति है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कारोबार का इस्तेमाल अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए एक कूटनीतिक हथियार की तरह कर रहे हैं। अमेरिका की इसी आक्रमकता का जवाब देने के लिए यूरोपीय संघ और भारत तेज़ी से मुक्त व्यापार समझौते की तरफ बढ़े हैं।

इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों में सैद्धांतिक सहमति बन गई है, लेकिन इसके प्रभावी होने में अभी लंबा वक़्त लग सकता है क्योंकि इसे क़ानूनी रूप देने के लिए यूरोपीय संघ की पार्लियामेंट और यूरोपीय परिषद में पारित करवाना है। बहरहाल, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं का भी संकेत देता है। यह डील ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है और अमेरिका भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लागू कर चुका है। लेकिन यूरोपीय संघ और भारत के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता अमेरिका को आर्थिक से ज़्यादा राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर असहज कर दिया। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार झुकना पड़ा और भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करना पड़ा। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि इससे पहले तक बातचीत बेनतीजा रही थी और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था।

यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि दबाव, मजबूरी और रणनीतिक बदलाव की भी मिसाल है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई बड़ी ट्रेड डील अहम वजह बनी। इस डील से भारत की ताकत बातचीत में बढ़ गई और अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं वह पीछे न छूट जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ

यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि दबाव, मजबूरी और रणनीतिक बदलाव की भी मिसाल है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे भारत और ईयू के बीच हुई बड़ी ट्रेड डील अहम वजह बनी।

दिन पहले ही भारत--ईयू डील को विकास, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़ा कदम बताया था। गौरतलब है, दुनिया को जब ट्रंप का टैरिफ वॉर झकझोर रहा था, तब भारत ने सीधे टकराव की बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। भारत ने अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशे। यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील, ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ समझौतों ने अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रंप को समझ आ गया कि भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ना एक बड़ी गलती थी। यह समझौता सिर्फ़ कारोबार तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके प्रभाव वैश्विक राजनीति पर भी होंगे, ख़ासकर अमेरिकी की आक्रामक कारोबार नीति पर। अमेरिका लंबे समय से भारत जैसे बड़े बाज़ार के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करना चाहता था, ताकि वह भारतीय बाजार से अधिकतम लाभ उठा सके। यूरोपीय संघ के साथ समझौता आगे बढ़ाने का भारत का फैसला उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। इसी कदम ने संभवतः अमेरिका को यह संकेत दिया कि अगर वह भारत के साथ समझौता जल्दी नहीं करता, तो उसे रणनीतिक और आर्थिक नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप को अपनी रणनीति भारत के खिलाफ बदलने पड़े। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों जैसे कि रूसी कच्चा तेल पर समझौता किए बिना भी वैश्विक शक्तियों के साथ बराबरी के स्तर पर व्यापार कर सकता है। नतीजा यह हुआ कि टैरिफ वॉर में भारत मजबूती से खड़ा रहा और आखिरकार झुकना अमेरिका को पड़ा। बहरहाल, यह समझौता भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक और चुनौतियां पेश भी करता है। भारत को अपनी निर्यात रणनीतियों और व्यापार समझौतों को इस बदलते सीन के अनुरूप ढालना होगा।

अगर अमेरिका और ईयू जैसे बड़े ब्लॉक द्विपक्षीय समझौतों पर फोकस करते हैं तो भारत को अपनी सप्लाई चेन को और अधिक लचीला और विविध बनाने की जरूरत होगी ताकि एक या दो प्रमुख बाजारों पर निर्भरता कम हो सके। ये समझौता भारत को अपने खुद के मुक्त व्यापार समझौतों को तेजी से अंतिम रूप देने और मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह ग्लोबल ट्रेंड भारत को 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से अपने स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है ताकि वह बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील बने।

कृषि उपज के लिए बाजार न खोलना बड़ी सफलता

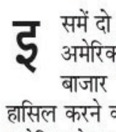

ट्रेड डील
उमेश चतुर्वेदी
राजनीतिक समीक्षक

इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बरसों से भारतीय कृषि बाजार में बड़ी और व्यापक पहुंच हासिल करने की कोशिश में है। हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान 18 प्रतिशत के ही टैरिफ पर उपलब्ध हो सकेंगे। शनिवार को जारी मसौदे के मुताबिक भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए नहीं खोला।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर मनमाने तरीके से थोपे गए पचास प्रतिशत के टैरिफ के मुकाबले मौजूदा व्यापार समझौते के तहत 18 प्रतिशत का टैरिफ कम ही कहा जाएगा। हालांकि अतीत के करीब तीन प्रतिशत के मुकाबले फिर भी यह बहुत ज्यादा है। बहरहाल, इसी समझौते के मद्देनजर जिस तरह से अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक लेस्ली रोलिंग्स ने खुशी जताई, उससे भारतीय किसान आशंकित हो उठे। भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। रोलिंग्स ने उम्मीद जताई कि नए व्यापार समझौते की वजह से विशाल आबादी वाला भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है। इसके चलते भारतीय किसानों का आशंकित होना जायज है। अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा पचास अरब डॉलर है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले। भारत की चिंता की वजह उसकी खेती-किसानी वाली बड़ी जनसंख्या है। भारत में खेती पर करीब 10.7 करोड़ परिवार निर्भर हैं। यह जनसंख्या का करीब बासठ प्रतिशत है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसने की अनुमति मिलती है तो भारी सब्सिडी के चलते भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। ऐसे में भारतीय किसानों के सामने संकट उठ खड़ा हो सकता है। हालांकि, कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का

इस समझौते से, भारतीय चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाजों को बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बाहर हैं।

कहना है कि भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। चौहान का यह भी कहना है कि इस कारोबारी समझौते से देश के मुख्य खाद्यान्नों, मिलेट्स, फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह अलग रखा गया है। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। भारत सरकार का दावा है कि नए टैरिफ समझौते से भारतीय किसानों के चावल और मसालों के साथ ही टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा।

समझौते के तहत भारत को अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर का सामान पांच सालों में खरीदना है। वैसे समझौते पर जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसके तहत भारतीय कृषि बाजार को भी खोलने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस समझौते से, भारतीय चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाजों को बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बाहर हैं। ऐसा करने की वजह यह है कि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग को कारोबारी परेशानियां न झेलनी पड़ें। वैसे भी भारत लंबे समय से कृषि और डेयरी उद्योग को 'रेड-लाइन' यानी किनारे रखने वाला सेक्टर मानता रहा है। इसकी वजह है कि गांवों में इनसे जुड़े काफी रोजगार हैं। इन सेक्टर को खोलने को लेकर भारत की बातचीत यूरोप और ब्रिटेन से भी अटक चुकी है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस बाजार को खोलना भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक तो होगा ही, राजनीतिक बवंडर की वजह भी बन सकता है। साल 2024 में भारत ने अमेरिका से 2.4 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद आयात किए थे, जिनमें ज्यादातर ताजे फल, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट मादक पेय, कच्चा कपास, वनस्पति तेल और प्रोसेस्ड सामान हैं। भारत ने अमेरिका को 6.2 अरब डॉलर का कृषि निर्यात किया, जिनमें समुद्री उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, जड़ी-बूटियों के आयुर्वेदिक उत्पाद प्रमुख रहे। यह भारत के कुल 53.2 अरब डॉलर सालाना के कृषि निर्यात का 11.74 प्रतिशत है। कृषि और डेयरी उत्पाद के कारोबार के इसी असुंलन की वजह से अमेरिका भारतीय बाजार में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सूत्र इससे साफ इनकार कर रहे हैं। भारत के सामने संकट यह है कि अगर उसने इस क्षेत्र को खोला तो छोटे और सीमांत किसानों के सामने जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनसे वह कैसे निबट पाएगा।

खबर संक्षेप

फुले की प्रतिमा तोड़ने वालों पर हो सख्तीः छगन

मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने तेलंगाना में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की निंदा की। उन्होंने इसे सामाजिक समानता की मूल भावना पर हमला बताया। भुजबल ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और दखल देने की मांग की। भुजबल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जैसलमेर में ट्रेन में धुएं से मची अफरा-तफरी

जैसलमेर। दिल्ली से जैसलमेर जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में रविवार सुबह अचानक अफरा-तफरी मच गई। यहां ट्रेन के एक कोच के पहियों से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। धुआं दिखाई देते ही लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

25 किलो हेरोइन जब्त, दो गिरफ्तार

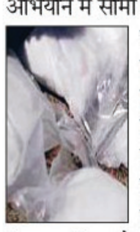

अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में सीमा पार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जखीरे के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने बताया कि बीएसएफ ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 25 किलो हेरोइन, 2 पिस्तौल और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पर बोला वस्त्र उद्योग मंत्रालय

118 अरब डॉलर के अमेरिकी बाजार का दरवाजा खुला, इससे निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ेंगे

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते ने भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा जरवाजा खोल दिया है। इस समझौते के बाद अमेरिका का 118 अरब डॉलर का आयात बाजार भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए ज्यादा सुलभ हो जाएगा। सरकार ने इसे निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया है। अमेरिका पहले से ही भारत के वस्त्र निर्यात का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा क ि इस समझौते से भारतीय वस्त्र और परिधान उत्पादों पर लगने वाला 18 प्रतिशत जवाबी शुल्क घटेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को कीमत के मामले में सीधा फायदा मिलेगा। मंत्रालय का कहना है कि अब भारत की स्थिति बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मजबूत होगी। बड़े अंतरराष्ट्रीय खरीदार भी अब अपनी खरीद रणनीति में भारत को प्राथमिकता दे सकते हैं।

1. भारतीय निर्यतकों को होगा सीधा फायदा
2. भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए होगा सुलभ
3. अन्य देशों की तुलना में भारत मजबूत होगा

भारतीय उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को भारत का मौजूदा वस्त्र निर्यात करीब 10.5 अरब डॉलर का है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा परिधान का और करीब 15 प्रतिशत मेड-अप्स का है। शुल्क घटने से भारतीय उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

2030 के निर्यात लक्ष्य में होगा सहायक

सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय का कहना है कि नया व्यापार समझौता इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। वस्त्र निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी पांचवें हिस्से से ज्यादा रह सकती है।

परिधान के साथ फुटवियर और रसायन क्षेत्र को मिलेगी राहत

इस अंतरिम व्यापार समझौते का फायदा सिर्फ कपड़ा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। परिधान, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर और रसायन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। आयात शुल्क घटने से इन सेक्टरों के उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग संगठनों का कहना है कि ऊंचे शुल्क के कारण हाल के महीनों में निर्यात प्रभावित हुआ था, अब स्थिति सुधर सकती है।

उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार में पहुंच आसान होगी

एमएसएमई और उपभोक्ताओं को सीधी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को स्पष्ट किया कि यह ढांचा भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार में पहुंच आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत कम होगी। टैरिफ के गणित को समझाते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका मौजूदा 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इसके बदले में, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क खत्म या कम करेगा। इन अमेरिकी उत्पादों में ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल हैं।

उधर, अटकलों का बाजार गरम
रूस से तेल खरीद में बड़ी कटौती करेगा भारत!

अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती के बदले हुए समझौते के तहत भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद धीरे-धीरे कम करने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हालांकि नायरा एनर्जी जैसी तेल शोधनशालाओं (रिफाइनरी) के पास सीमित विकल्प होने के कारण ये आयात फिलहाल पूरी तरह बंद नहीं होंगे। जानकारों ने बताया कि तेल शोधनशालाओं को रूस से खरीद रोकने का कोई औपचारिक निर्देश नहीं मिला है।

समझौते पर बोले शाह
मेक इन इंडिया और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को देश के तेज रफ्तार विकास इंजन को नया बल देने वाला कदम बताया है। 'एक्स' पर उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में अहम है और इससे 'मेक इन इंडिया', किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप तथा मछुआरों को लाभ मिलेगा। युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

तेलंगाना स्पीकर को अंतिम चेतावनी
विधायकों की अयोग्यता पर 3 हफ्ते में लें फैसला, नहीं तो कार्यवाही शुरू

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि वो भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी शेष अयोग्यता याचिकाओं पर तीन सप्ताह के अंदर निर्णय लें। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से कहा कि इस मामले पर रील्स न बनाएं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच शुक्रवार को 31 जुलाई 2025 के अपने उस आदेश के अनुपालन की समीक्षा कर रही थी, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अवधि में निर्णय न लेने के कारण कोर्ट में अवमानना याचिकाएं दायर की गई थीं।

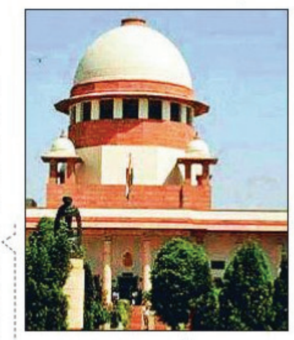

राज्य सरकार ने मांगा 3 सप्ताह का समय

गौरतलब है कि 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी (तेलंगाना राज्य की ओर से) ने दो सप्ताह का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने यह उम्मीद जताते हुए मंजूर किया था कि कुछ प्रगति होगी। आज सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि एक मामले में फैसला हो चुका है, जबकि शेष दो मामलों में निर्णय आसन्न है और इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि नगरपालिका चुनावों के कारण समय लगा और दूसरी ओर से भी समय मांगा गया था।

याचिकाकर्ता ने किया विरोध

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने फिर से समय दिए जाने का विरोध किया और कहा कि स्पीकर पहले ही तीन बार समय ले चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ा जा रहा है और केवल एक ही सुनवाई क्यों हुई, यह सवाल उठाया। उनके अनुसार, कुछ मामलों में तथ्य निर्विवाद हैं- जैसे एक विधायक का कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ना/हारना और दूसरे मामले में विधायक की बेटी का कांग्रेस से जीतना-तो फिर निर्णय में देरी क्यों। 9 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट की एकल बेंच ने स्पीकर को चार सप्ताह में सुनवाई का कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया था। नवंबर 2024 में डिवीजन बेंच ने यह आदेश रद्द करते हुए कहा कि स्पीकर को उचित समय में निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं की अपील पर, जुलाई 2025 में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश रद्द कर स्पीकर को तीन महीने में निर्णय करने का निर्देश दिया था।

एसडीएम मोनालिसा जौहरी के कार्यों की जिलाधिकारी ने की सराहना

बहराइच। तहसील नानपारा में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई के उपरान्त जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा तहसील नानपारा का औचक निरीक्षण कर अभिलेखों के रख-रखाव, भवन एवं परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ तहसील अन्तर्गत संचालित विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर न्यायिक कार्यों, वादो का निस्तारण, राजस्व अभिलेखों, वसूली, अभिलेखागार, आईजीआरएस एवं जनसुनवाई इत्यादि व्यवस्था का गहनता से परीक्षण किया गया। एसडीएम न्यायालय में दर्ज वादों की स्थिति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 01 वर्ष से अधिक अवधि का कोई भी वाद लंबित नही है। पत्रावलियों के अवलोकन प्रथम द्दष्टया समस्त धाराओं के वादों का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण पाया गया। इस स्थिति पर डीएम ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसील नानपारा में प्रशासनिक एवं न्यायिक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। डीएम ने तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के न्यायालयों का निरीक्षण करते हुए प्रचलित वादों का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व वसूल की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की स्थिति बेहतर पायी गयी। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि नियमित रूप से समीक्षा करती रहें

गोगोई मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सरमा का दावा
पाकिस्तान से सीधे संबंधों के मिले सबूत, एमएचए करे जांच
इसमें सियासत और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति हो गई तेज

एजेंसी ▶▶ गुवाहाटी

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में सियासत और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है।असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एसआईटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दावा किया है कि एसआईटी रिपोर्ट में अली तौकीर शेख एलिजाबेथ गोगोई और गौरव गोगोई तीनों के पाकिस्तान से सीधे संबंध होने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखकर कैबिनेट मंत्री भी हैरान रह गए। सरमा ने कहा कि असम पुलिस की एसआईटी ने इस मामले की जांच की और रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अब इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाएगी।

केंद्रीय एजेंसी से जांच को लिखा

गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान से संबंध

सरमा ने गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सीएम का कहना है कि गौरव की पत्नी के पाक से संबंध रहे हैं। एलिजाबेथ मार्च 2011 से मार्च 2012 तक पाक में काम कर चुकी हैं। उनके परिवार के संबंध अली तौकीर शेख के साथ बहुत घनिष्ठ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के हितों के लिए काम करता रहा है।

पाकिस्तान दूतावास की तस्वीर का जिक्र

सरमा ने एक पुरानी तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें गौरव कुछ युवाओं को लेकर भारत में पाकिस्तान के दूतावास गए थे। उस समय भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित थे।

गोगोई ने हिमंता पर साधा निशाना
यह सी-ग्रेड फिल्म से भी बदतर

गौरव गोगोई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर मुझे तरस आता है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। यह किसी सी-ग्रेड फिल्म से भी बदतर थी। मुख्यमंत्री ने बेहद बेतुके और झूठे तर्क दिए। यह सुपरफ्लॉप हमारी 'यात्रा' के बिल्कुल विपरीत है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्जा की गई 12,000 बीघा जमीन का पर्दाफाश करने में सफल रही है।

यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा
बस से उतरे कई यात्रियों को कंटेनर ने कुचला, 6 की मौत

एजेंसी ▶▶ मथुरा

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 88 के निकट कंटेनर द्वारा कुचलने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के करीब 2:45 बजे हुआ। यात्री बस से नोएडा से आगरा की ओर जा रहे थे और बस रुकने पर लघु शंका को उतरे थे। बस नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी। बस रुकने पर यात्री उतरकर लघु शंका के लिए जा रहे थे, तभी एक कंटेनर ने यात्रियों को कुचल दिया। एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने कंटेनर के नीचे से सभी को निकाला। हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव जिला जशपुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202602031100004
विषयः-अ-2
मामले की श्रेणीः- राजस्व
सनः-2025-2026
पत्थलगांव प.ह.न. 00006 [88/1/5(0.0240 हे0) 1
पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार आशीष कुमार पिता रामलाल अग्रवाल,
अनावेदक पक्षकार - छ.ग. शासन,
ईश्तहार

एतद द्वारा समस्त आम जनता ग्राम पत्थलगांव प.ह.न. 06 तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री आशीष कुमार पिता रामलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी ग्राम पत्थलगांव तहसील पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) के द्वारा ग्राम पत्थलगांव प.ह.न. 06 रा.नि.मं. पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) स्थित भूमि ख.नं. 88/1/ड रकबा 0.024 है, (240 वर्गमीटर) भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ (मकान निर्माण) के लिये व्यपवर्तन कराये जाने हेतु बी-1 नक्शा खसरा एवं रजिस्ट्री की छाया प्रति सहित छ.ग.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 को स्थान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव के न्यायालय में न्यायालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक होना नियत किया गया है, अतः इसमें जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे नियत दिनांक/समय स्थान को मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रतिवेदन एवं प्रयोजनार्थ ले-आउट नगर निवेश जशपुर से अनुमोदनार्थ सहित समयावधि में दिनांक 25.02.2026 तक जमा करें, अन्यथा शासनादेषानुसार निराकरण किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/02/2026 को जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
पत्थलगांव जिला जशपुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202602020700094/

विषयः- अ-6
मामले की श्रेणीः- राजस्व
सनः-2025-2026
फुन्दुरडिहारी प.ह.न. 00016 [395/2(0.0400हे०)] पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार दीपा तिर्की

अनावेदक पक्षकार -जगजीत मिंज,
ईश्तहार

आवेदक दीपा तिर्की पनी नेस्तोर तिर्की निवासी वार्ड नंबर 3. अटल आवास के पीछे, उसलापुर बिलासपुर जिला बिलासपुर छ०ग के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 395/2 मेसे रकबा 0.040 है० भूमि के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.06.1999 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27.02.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/02/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
तहसील- अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला- सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क. /अ-6/2025-26 /202602021700020
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका दीपा तिर्की पत्नी श्री नेस्तोर तिर्की व अन्य, निवासी ग्राम उसलापुर बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ०ग० द्वारा ग्राम अजिरमा स्थित भूमि खसरा नंबर 458 में से रकबा 0.070 हे० भूमि पर से विक्रेता बुधियारो आ. अघनू व अन्य, जाति गोड़, निवासी ग्राम अजिरमा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर से दिनांक 22.05.1999 को पंजीबद्ध विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया है, आवेदिका द्वारा पंजीबद्ध विकय पत्र के आधार पर नामांतरण बावत आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 4/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन प्रदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला- सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क० / अ-6/2025-26 202602021700019
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निखिल तिर्की आ. नेस्तोर तिर्की व अन्य, निवासी ग्राम उसलापुर बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ०ग० द्वारा ग्राम अजिरमा स्थित भूमि खसरा नंबर 457/1 में से रकबा 0.060 हे० भूमि पर से विक्रेता धनेश्वरी पत्नी गिरधारी व अन्य, जाति गोड़, निवासी ग्राम अजिरमा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर के पूर्वज गिरधारी पिता बोधन से दिनांक 29.05.2005 को पंजीबद्ध विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया है, आवेदक द्वारा पंजीबद्ध विकय पत्र के आधार पर नामांतरण बावत आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 04/02 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिसत तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202602020700093/
विषयः-अ-6
मामले की श्रेणीः राजस्व
सनः-2025-2026
फुन्दुरडिहारी प.ह.न. 00016 [377/3(0.0720हे0)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार दीपा तिर्की,
अनावेदक पक्षकार -जीवन लकड़ा,
ईश्तहार

आवेदक दीपा तिर्की पत्नी नेस्तोर तिर्की निवासी वार्ड नंबर 3. अटल आवास के पीछे, उसलापुर बिलासपुर जिला बिलासपुर छ०म० के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 377/3 मेसे रकबा 0.072 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2005 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27.02.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/02/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
तहसील- अम्बिकापुर

श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा अंतर्गत लगा मुफ्त स्वास्थ्य कैंप

रूपईडीहा, बहराइच। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध प्रान्त एवं श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के छठवें संस्करण की शुरूआत 6झ7 फरवरी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों के साथ हुई। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित थारू जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आयोजित इस स्वास्थ्य मेले की श्रृंखला प्रदेश के सात जिलों में एक साथ प्रारंभ हुई। बहराइच जनपद के बाबागंज क्षेत्र में लगभग 16 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय एवं बाहरी चिकित्सकों सहित लगभग 56 डॉक्टरों ने सहभागिता की। सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित शिविरों में विभिन्न सामाजिक संगठनों—एकल अभियान, सीमा जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती आदि के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। चिकित्सकों ने स्थानीय संस्कृति को समझने के उद्देश्य से ग्रामीण परिवारों के घरों में रात्रि विश्राम भी किया। स्वास्थ्य शिविरों के दौरान चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया तथा संतुलित आहार, माहवारी स्वच्छता सहित विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक इस स्वास्थ्य सेवा यात्रा के माध्यम से 4860 से अधिक लोगों ने लाभ प्राप्त किया, जिनमें 2540 महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य शिविरों में उत्साहपूर्वक भाग लिया, वहीं चिकित्सकों के लिए भी यह अनुभव अनूठा और प्रेरणादायक रहा। इस यात्रा के अंतर्गत 8 फरवरी को किसान पीजी कॉलेज, बहराइच में विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह स्वास्थ्य सेवा यात्रा पिछले छह वर्षों से निरंतर संचालित हो रही है और प्रत्येक वर्ष नए आयाम स्थापित कर रही है।

नाम परिवर्तन

मैं उमाशंकर आ. राजनाथ, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम वरपारा चलगली, पो० पटोरा, थाना व तहसील लुण्ड्रा, जिला सरगुजा, छ.ग. का स्थायी निवासी हूँ जो निम्न कथन शपथपूर्वक करता हूँ कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम सुस्वन्ती दर्ज हो गया है और मेरी पुत्री का आधार कार्ड नं० 5884 6086 8286 है। यह कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में भारती अंकित है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरे पुत्री का नाम सुधार कर सही नाम जो कि भारती अंकित किया जाये, जिसके समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता- उमाशंकर आ. राजनाथ, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम वरपारा चलगली, पो० पटोरा, थाना व तहसील लुण्ड्रा, जिला सरगुजा, छ.ग.

भारत की संस्कृति का आभूषण है बस्तर - केंद्रीय गृहमंत्री

बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का कार्य कर रही छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर भारत की संस्कृति का आभूषण है। बस्तर पण्डुम के माध्यम से यहां की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को छत्तीसगढ़ सरकार ने नए प्राण देने का काम किया। बस्तर पंडुम 2026 के सभी विजेताओं को केंद्रीय गृहमंत्री शाह और मुख्यमंत्री साय ने सम्मानित किया। केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोक कलाकारों को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने और सहभोज करने का अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने जनजातीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन तथा जनजातीय प्रकृति व परंपरा का उत्सव बस्तर पण्डुम के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय आयोजन के समापन अवसर पर आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग के 07 जिले के 32 जनपद पंचायतों और 1885 ग्राम पंचायतों के 53 हजार से अधिक लोक कलाकारों ने 12 विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन्हीं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य बस्तर पण्डुम 2026 के माध्यम से राज्य की सरकार द्वारा किया जा रहा है।

आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को पुनर्जीवित करने धरती आबा योजना

श्री शाह ने कहा कि बस्तर जैसी संस्कृति विश्व के किसी देश में नहीं है और इसे प्रभु श्री राम के समय से संजोकर यहां के लोगों ने अक्षुण्ण बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 700 से अधिक जनजातियों की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को पुनर्जीवित करने धरती आबा योजना और पीएम जनमन योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की। श्री शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं बल्कि यहां की भोली-भाली आदिवासी जनता को सुरक्षा देना है। माओवाद उन्मूलन की समय सीमा अभी भी वही है। जवानों के अदम्य साहस और बहादुरी से 31 मार्च 2026 तक हो माओवाद को घुटने टेकने पड़ेंगे। उन्होंने प्रदेश में संचालित की जा रही नक्सल पुनर्वास नीति की सराहना करते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्रों में उन्हें रोजगारमूलक और सृजनात्मक गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है।

40 गांवों के स्कूलों में गोलियों की आवाज की जगह स्कूल की घंटियां सुनाई देती है

केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत प्रदेश सरकार लगातार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोडमैप तैयार कर सड़क, पुल पुलिया, मोबाईल टॉवर स्थापित करने के साथ-साथ राशन वितरण, शुद्ध पेयजल, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना रही है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित गांवों में लाल आतंक के चलते विकास से कोसों दूर थे, वहां के 40 गांवों में स्कूल फिर से खोले गए। अब वहां गोलियों की आवाज की जगह स्कूल की घंटियां सुनाई देती हैं।

दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में 02 लाख 75 हजार एकड़ जिले में सिंचाई के लिए 220 मेगावॉट बिजली उत्पादन का कार्य शीघ्र प्रारंभ

श्री शाह ने मंच से जानकारी दी कि बस्तर जिले में 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा तथा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में 02 लाख 75 हजार एकड़ में सिंचाई के लिए 220 मेगावॉट बिजली उत्पादन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वहीं दूरस्थ अंचलों को मुख्यालयों से जोड़ने के लिए रेल परियोजनाओं और नदी जोड़ो परियोजना को विस्तार दिया जाएगा।

बस्तर पंडुम एक आयोजन बस नहीं है, यह बस्तर की पहचान का उत्सव- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माता दंतेश्वरी से ही बस्तर की पहचान है। बस्तर पंडुम एक आयोजन बस नहीं है, बल्कि यह बस्तर की पहचान का उत्सव है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के प्रति गृह मंत्री अमित शाह के स्नेह और लगाव के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी श्री शाह की मौजूदगी ने बस्तरवासियों का हौसला बढ़ाया था और आज फिर उनकी उपस्थिति ने कलाकारों और यहां के लोगों में नई ऊर्जा भर रही है।

समृद्ध संस्कृति को देश-दुनिया के सामने लाने बस्तर पंडुम का आयोजन

श्री साय ने कहा कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश- दुनिया के सामने लाने बस्तर पंडुम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों, प्रतिभागियों को बधाईयां। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 47 हजार कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भाग लिया और इस वर्ष 54 हजार से अधिक कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और बस्तर की संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा, स्थानीय साहित्य, लोकनृत्य, गीत, शिल्प, बस्तरिया पेय, औषधि चित्रकला, वाद्ययंत्र, नाटक की विद्या सहित 12 विद्याओं का प्रदर्शन कलाकारों के द्वारा किया गया। बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम किया गया।

बस्तर के विकास की चर्चा देश भर में

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बस्तर अब संभावनाओं की भूमि बन चुकी है। यह नए भारत का नया बस्तर है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बस्तर के विकास की चर्चा देश भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले बस्तर की चर्चा देश भर में माओवादी के नाम से होती थी, किन्तु अब बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और समृद्ध विरासत की चर्चा होने लगी है।

बस्तर तरक्की की एक नई सुबह देखने को मिल रही है

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर की सुंदर धरती लंबे समय तक नक्सलवाद की पीड़ा से गुजरी है। गौर, माड़िया, मुरिया, भतरा, धुरवा, गोंड जैसे विभिन्न नृत्य की लय धीमी पड़ गई थी, मांदर की थाप खामोश हो गई थी, लेकिन आज बस्तर बदल रहा है। यहां तरक्की की एक नई सुबह देखने को मिल रही है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे।

आत्म समर्पण नीति के तहत सम्मान के साथ पुनर्वास

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने घने जंगलों में, विपरीत परिस्थितियों में, अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। नियद नेल्ला नार - (आपका अच्छा गांव) योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं गांव में पहुंचाई हैं। आत्मसमर्पण नीति को और अधिक मानवीय और संवदेनशील बनाया है, जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनका सम्मान के साथ पुनर्वास कराया जा रहा है।

पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में भी बस्तर के विकास की चर्चा की। श्री साय ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है। धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जाना हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म, होम-स्टे, ट्रेकिंग जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सतत पर्यत्नशील है, जिससे बस्तर ही नहीं छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की जानकारी पर्यटकों को मिल सके और पर्यटन छत्तीसगढ़ की ओर आर्कर्षित हो सके। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर पांडुम के भव्य आयोजन से बस्तर की समृद्ध और विशिष्ट जनजातीय संस्कृति की सराहना करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और स्थायी शांति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत विश्व में अद्वितीय है। उन्होंने छेरछेरा पंडुम, तिहार और विजा पंडुम जैसे पारंपरिक उत्सवों को जनजातीय जीवन, प्रकृति और कृषि से जुड़ी अमूल्य परंपराएं बताया। नक्सलवाद पर दृढ़ प्रहार की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बस्तर के दूरस्थ और उपेक्षित क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय ध्वज की उपस्थिति पहुँची है, जो विकास और विश्वास की नई शुरूआत है। श्री शर्मा ने बस्तर पांडुम को समाज-नेतृत्वत आयोजन बताते हुए कहा कि इसके असली सूत्रधार मांझी-चालकी, गयाता और पुजारी जैसे पारंपरिक समाज प्रमुख हैं, जिनके सहयोग से बस्तर पंडुम का आयोजन सफल हुआ। उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी के प्रति आभार प्रकट किया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बस्तर पंडुम 2026 के उद्देश्य और 12 विद्याओं पर भाग लेने वाले कलाकारो की विस्तृत जानकारी दी, और कहा कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-विदेश तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, पद्मश्री अजय मंडावी, श्रीमती बुधरी ताती, हेमचंद मांझी, पंडीराम मांझी, सांसद भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी सहित जनप्रतिनिधिगण, गायता, पुजारी, मांझी-चालकी, बस्तर पंडुम के कलाकार, महापौर संजय पांडे, कमिश्नर डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी, कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

माँ दंतेश्वरी की धरती पर संस्कृति का उत्सव, बस्तर पंडुम ने जीता दिल

सुकमा के जनजातीय वेशभूषा ने बिखेरा जलवा, गुंजन नाग और किरण नाग ने बढ़ाया जिले का मान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। बस्तर की आत्मा, उसकी परंपराएं और उसकी जनजातीय पहचान इन सबका भव्य उत्सव बनकर उभरा बस्तर पंडुम 2026ह्व न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन रहा, बल्कि यह सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनजातीय संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण भी बना। लाल बाग मैदान में हुए इस ऐतिहासिक समापन समारोह ने पूरे देश का ध्यान बस्तर की गौरवशाली विरासत की ओर आकृष्ट किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की परिकल्पना को प्रशासन ने पूरी निष्ठा के साथ साकार किया। यह आयोजन उन परंपराओं के लिए संजीवनी साबित हुआ, जो समय के प्रवाह में विलुप्त होने की कगार पर थीं। पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, जनजातीय वेशभूषा, खानपान और शिल्प सब कुछ अपने मूल स्वरूप में सहेजा गया, यही इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

सुकमा बना सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक

सुकमा जिला प्रशासन ने इस आयोजन में उत्कृष्ट समन्वय, प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का परिचय दिया। जिले के कलाकारों ने बस्तर की आत्मा को मंच पर जीवंत कर दिया। छिंदगढ़ विकासखंड के किंदरवाड़ा निवासी गुंजन नाग और किरण नाग ने जनजातीय वेशभूषा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल सुकमा, बल्कि पूरे बस्तर का मान बढ़ाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन चेक प्रदान किया गया, जो शासन की कलाकारों के प्रति सम्मान और विश्वास को दशार्ता है।

सहभागिता ने रचा इतिहास

सुकमा जिले से 12 विधाओं में 69 कलाकारों की सहभागिता ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए मंच और अवसर जनजातीय प्रतिभाओं को नई उड़ान दे रहे हैं। यह सहभागिता केवल प्रस्तुति नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और भविष्य की उम्मीद का प्रतीक रही।

स्कूली बच्चों की प्रस्तुति से प्रभावित हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह, ताली बजाकर बढ़ाया उत्साह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। संभाग स्तरीय बस्तर पण्डुम 2026 के समापन समारोह में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और ताली बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री के स्वागत में जगदलपुर के हजारों स्कूली बच्चों ने ऐसा जादू है मेरे बस्तर मेंह्व गीत पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बच्चों की भावपूर्ण और अनुशासित प्रस्तुति देखकर अमित शाह भी भावविभोर हो उठे और उन्होंने बच्चों को ताली बजाकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा मलखंभ प्रदर्शन भी किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने बच्चों की कला, अनुशासन एवं आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

अमित शाह ने देखा बस्तर की जनजातीय विरासत का वैभव, विजेता दलों से मिलकर बढ़ाया उत्साह

बस्तर पंडुम में दिखी आदिवासी जीवन की झलक, प्रदर्शनी देखकर मंत्रमुग्ध हुए केंद्रीय गृहमंत्री

जनजातीय संस्कृति की अनूठी पहचान बना बस्तर पंडुम, विजेताओं को मिला सम्मान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर जनजातीय समाज के जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों, हस्तशिल्प और कलाओं की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीसल कला, बांस व लौह शिल्प, जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण, तुम्बा कला, जनजातीय चित्रकला, वन औषधि, स्थानीय व्यंजन तथा लोक चित्रों पर आधारित प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति भारत की आत्मा का जीवंत स्वरूप है। प्रदर्शनी में दंडामी माड़िया, अबूझमाड़िया, मुरिया, भतरा एवं हल्बा जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों का प्रदर्शन किया गया। जनजातीय चित्रकला के माध्यम से आदिवासी जीवन, प्रकृति और परंपराओं की सजीव झलक प्रस्तुत की गई। वहीं, वैद्यराज द्वारा वन औषधियों का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया। स्थानीय व्यंजन स्टॉल में जोंधरी लाई के लड्डू, मंडिया पेज, आमट, चापड़ा चटनी, कुलथी दाल, पान बोबो, तीखुर जैसे पारंपरिक व्यंजन तथा लांदा और सल्फी पेय पदार्थ प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर पंडुम जनजातीय संस्कृति को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार जनजातीय कला, शिल्प और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है ।ह्व इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर पंडुम की बारह विधाओं की प्रतियोगिता में विजेता दलों से भेंट कर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण सिंह देव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुकमा के जनजातीय नाट्य ने बिखेरा जलवा, मुड़िया जनजाति पर आधारित नाट्य का मंचन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। बस्तर संभाग की गौरवशाली संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण हेतु आयोजित 'बस्तर पंडुम 2026' में सुकमा जिले ने सफलता का परचम लहराया है। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित इस भव्य संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सुकमा के जनजातीय नाट्य दल विधा को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। देश के गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा के कलाकारों को स्मृति चिन्ह और 50 हजार रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया।

संस्कृति के संरक्षण की अनूठी पहल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बस्तर के पारंपरिक नृत्य, गीत, खानपान, शिल्प और आंचलिक साहित्य के मूल स्वरूप को सहेजना और स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। प्रशासन की इस पहल से न केवल विलुप्त हो रही विधाओं को संजीवनी मिल रही है, बल्कि जनजातीय समूहों के सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।

सुकमा के कलाकारों ने जीती प्रतियोगिता

कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन और जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर के कुशल प्रबंधन में सुकमा जिले से 12 विधाओं के कुल 69 कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रथम स्थान कोंटा विकासखंड के सुदूर ग्राम पंचायत कोंडासांवली के आश्रित गांव पारला गट्टा की टीम ने नाट्य विधा में बाजी मारी।

कला का जीवंत चित्रण

मुड़िया जनजाति के 13 सदस्यीय दल (9 पुरुष, 4 महिला) ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे ताड़ का पत्ता, मयूर पंख, तीर-धनुष और मछली पकड़ने के जाल का कलात्मक प्रयोग कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इन कलाकारों ने बढ़ाया जिले का गौरव

कोंटा विकासखंड में स्थित पारला गट्टा निवासी कलाकार लेकम लक्का, प्रकाश सोड़ी, विनोद सोड़ी, जोगा सुदाम और उनकी टीम ने अपनी प्रतिभा से सुकमा जिले को गौरवान्वित किया है। कलाकारों की इस सफलता में नोडल अधिकारी मनीराम मरकाम और पी श्रीनिवास राव का विशेष योगदान रहा जिन्होंने कलाकारों को संभाग स्तर तक पहुंचाने और प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई।

जी राम जी योजना पर हुआ एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के प्रेमनगर जनपद सभाकक्ष में सोमवार को विकसित भारत जी राम जी योजना पर आधारित कार्ययोजना के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में आयोजित उखत कार्यशाला में जनपद अध्यक्ष फुलेश्वर सिरदार, उपाध्यक्ष श्रीमती पुनिया राजवाड़े, जनप्रतिनिधि शिवनंदन मरावी, विजय सिरदार, महेन्द्र यादव, जनपद सदस्य, सरपंच, जनपद सीईओ शिव कुमार टंडन, कार्यक्रम अधिकारी राजेश्वर गुप्ता तथा सचिव, रोजगार सहायक एवं समस्त तकनीकी सहायक सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गांरटी मिशन ग्रामीण 2025 की मुलभूत जानकारी योजना की तकनीकी जानकारी राष्ट्रिय डिजीटल प्लेटफार्म मैपिंग कार्यों का चयन प्रक्रिया युक्तधारा में एण्ट्री किया जाना के संबंध में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचातय प्रेमनगर व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा योजनाओं के बेहतर और प्रभावी। क्रियान्वयन के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति दी गई।

लक्ष्य अनुरूप विभागीय योजनाओं की प्रगति करें हासिल : कलेक्टर

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सोमवार को यहां जिला संयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आहूत की गई। जिसमे शासन के विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं एवं विभागीय कार्यों के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन में लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल करने की बात कही गई। उन्होंने मुख्य सचिव विकासशील द्वारा दिये गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 18 फरवरी तक संचालित होने वाले वजन त्यौहार का सुचारू व प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

बैठक में आज अग्रसेन भवन भैयाथान में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह के संबंध में चर्चा भी की गई। योजना के तहत 250 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाना है, जिसके तैयारियों के संबंध में कलेक्टर द्वारा महिला एवं बाल विकास

विवाह के जिला कार्यक्रम अधिकारी से तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई। इसके साथ ही कार्यक्रम को सफल संपादन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, सर्व एसडीएम व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिला खनिज संस्थान न्यास प्रबंधकारिणी समिति की हुई बैठक

जिला खनिज संस्थान न्यास प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में कलेक्टर द्वारा वित्तिय वर्ष 2025-26 हेतु सेक्टरवार कार्ययोजना के आबंटन, स्वीकृति कार्यों की विधानसभावार, वर्षवार स्वीकृति कार्यों की सेक्टरवार संख्यात्मक जानकारी, जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत अंशदान एवं न्यास निधि में उपलब्ध राशि व निरस्त कार्यों के संबंध में बिंदुवार चर्चा की गयी। बैठक में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध और दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास और आजीविका सृजन, स्वच्छता, आवास, कृषि, पशुपालन, अन्य जनकल्याणकारी योजना पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की बात कही गयी। इसके साथ ही परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर, सरपंच देंगे बच्चो को नगद इनाम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। 10 वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले परशुरामपुर स्कूल के छात्र, छात्राओ को गांव के सरपंच ने प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम परशुरामपुर के सरपंच मीरा लालकेश्वर सिंह ने गांव में संचालित हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में पहुँचकर छात्रों से ईमानदारी व धैर्य पूर्वक परीक्षा देने का आग्रह किया है।

उन्होंने बच्चो को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह परीक्षा आपके जीवन को बेहतर और प्रेरणा दायक साबित करने वाला होगा, अपने मन से डर को हटाते हुए बगैर किसी घबराहट प्रश्नों को अच्छे से पढ़ कर उसका उत्तर लिखें ताकि आप सभी अच्छे अंक अर्जित कर गांव व जिला का नाम रौशन कर सके। उन्होंने कहा कि बेहतर अंक अर्जित करने वाले सभी छात्र छत्राओ को प्रशस्तिपत्र के साथ कक्षा 10 वीं के बच्चो को 11 सौ नकद एवं 12वीं के बच्चों को 21 सौ रुपये का पुरुस्कार स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाएगा वहीं उनके माता पिता को शाल श्रीफल से सम्मानित करने घोषणा की है।

सरपंच द्वारा छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उक्त पुरुस्कार विगत वर्षों से दे रहे है।

फेयरवेल की खुशी पर भारी पड़ा हुड़दंग, छात्रों की स्टंटबाजी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर में संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को आयोजित कक्षा 12 वीं के फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब कुछ छात्रों ने खुशी के जश्न को कानून और अनुशासन की सीमाओं से बाहर निकाल दिया। महंगे चारपहिया वाहनों में हूटर बजा स्टंटबाजी करते हुए निकाली गई रैली ने न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला, बल्कि स्कूल प्रशासन की सख्त हिदायतों को भी खुली चुनौती दे दी।

जानकारी के अनुसार डीएवी पब्लिक स्कूल बिश्रामपुर में फेयरवेल कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों और अभिभावकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अभिभावकों के मोबाइल पर भेजे गए संदेशों में छात्रों को निजी वाहनों से स्कूल न भेजने, किसी भी प्रकार की हूटिंग, हुड़दंग या अनुशासनहीनता से दूर रहने की सख्त अपील की गई थी। बावजूद इसके कुछ शरारती प्रवृत्ति के छात्र इन निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए चारपहिया वाहनों से विद्यालय पहुंचे। कार्यक्रम में स्थिति तब बिगड़ गई, जब इन्हीं छात्रों ने विद्यालय परिसर से निकलकर मुख्य बाजार और आसपास की कॉलोनियों में चारपहिया वाहनों की रैली निकाल दी।

रैली के दौरान तेज आवाज में हूटर बजाए गए और सड़कों पर खतरनाक स्टंट किए गए, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही बिश्रामपुर पुलिस हरकत में आकर मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर

कई वाहन चालक अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने पांच चारपहिया वाहनों को मौके से जब्त कर लिया। जब्त किए गए वाहनों में क्रमांक सीजी 29 एजे 1811, सीजी 15 सीवी 901, सीजी 15 सीक्यू 5577, सीजी 08 एई 9200 एवं सीजी 04 क्यूई 2830 शामिल हैं। सभी वाहनों को थाने ले जाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में प्रभारी थाना प्रभारी विशुन देव पैकरा ने बताया कि मामले में शामिल नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों को थाने तलब किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

पुलिस ने यह भी संदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्टंटबाजी और हूटर का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बनी हुई है कि फेयरवेल जैसे गरिमामय आयोजन को कुछ छात्रों की लापरवाही और दिखावे की प्रवृत्ति ने बदनाम कर दिया है।

प्रा. शा. उरांवपारा में परीक्षा पे चर्चा का हुआ सीधा प्रसारण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शासकीय प्राथमिक शाला उरान्वपारा मदनेश्वरपुर मे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को तनाव से दूर रहने के लिए बीते हुवे परीक्षा को ध्यान मे रखें, याद करें परीक्षा देकर परीक्षा हॉल से बाहेर निकलने पर कैसा फील होता है, कितना आसान लगता है उसी सोच को पहले से रखे और तनाव को दूर रखें, नींद पूरी लें किसी प्रकार तनाव नहीं होगा।

आदिवासी बच्चे आज बहुत से क्षेत्र मे आगे आ रहें हैँ सभी बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, कला है, खेल के क्षेत्र मे आगे बढ़ सकते हैँ, उनके द्वारा मध्यप्रदेश के महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ का जिक्र किया गया। एक आदिवासी लड़की कितनी प्रतिभाशाली है, वैसे आप सबमे प्रतिभा है, परीक्षा को तनाव से ना जोड़कर एक पड़ाव कि तरह सोचे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को परीक्षा के तनाव से दूर रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुवे परीक्षा कि तैयारी हेतु मनोभाव विकसित करना है।कार्यक्रम के दौरान प्रधान पाठक संजय साहू बच्चों से चर्चा भी करते रहें कि परीक्षा को लेकर मानसिक तनाव और भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनाव कि

स्थिति मे याद किये हुए प्रश्न भी भूल जाने कि सम्भावना रहती है। सबसे ज्यादा जरुरी बात परीक्षा पे चर्चा मे अनुशाशन और समय पाबंदी पर ध्यान देने हेतु कहा गया, यदि आपके अंदर अनुशासन है और समय के प्रति पाबंद हैँ तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होंगी। नियमित अभ्यास, बार बार केवल प्रश्न उत्तर को पढ़े नहीं, बल्कि उनके उत्तर बार बार लिखकर अभ्यास करें इससे आपके अंदर आत्माविस्वास आएगा। इस अवसर पर विद्यालय मे प्रधानपातक संजय साहू, शिक्षक रामकृपाल साहू, शिक्षिका एनिमा बेक उपस्थित रही, बच्चों को कुछ बाते जो समझ नहीं आती उन्हें शिक्षकों द्वारा समझाया जाता रहा। उपस्थित शिक्षकों ने परीक्षा पे चर्चा को एक सकारात्मक और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी बताया, और कहा इससे बच्चों मे आत्माविश्वास आता है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में संशोधन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सूरजपुर जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2026-27 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नवीन प्रवेश दिशा - निर्देश के तहत सूचना जारी करते हुए ऑनलाइन पोर्टल https:\\eklavya.cg.nic.in के माध्यम से 07 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था।

जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी को किया गया था, अब वर्तमान में 11 फरवरी को निर्धारित तिथि किया गया है। और ऑनलाइन भरे गये आवेदन में त्रुटि सुधार 08 से 10 फरवरी तक किया गया था। अब वर्तमान में 12 से 14 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। इसमें प्रवेश परीक्षा 01 मार्च रविवार प्रात: 10:00 बजे से 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

पीएम आवास (ग्रामीण) नहीं बनाने वाले हितग्राहियों की एसडीएम ने की पेशी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पीएम आवास ग्रामीण अंतर्गत राज्य शासन एवं कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन व सीईओ जिला पंचायत श्री विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन हो रही है। राज्य स्तर पर विगत 10 माह में 5 लाख से अधिक आवास निर्मित हुए है एवं जिले से 18 हजार से अधिक आवास पूर्ण हुए है।

शासन स्तर से पूर्णता के लिए शेष बचे हितग्राहियों के आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

उक्त परिपालन में अधिकतर हितग्राही कार्य को गति दे रहे है। किंतु कुछ ऐसे भी हितग्राही है जो आवास निर्माण के लिए राशि लेकर कार्य नहीं करा रहे है। इन्हें बार बार समझाइस एवं

नोटिस देने के उपरांत अंततः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रशि कराई जा रही है। एसडीएम रामानुजनगर श्री अजय मोडियम के द्वारा आवास निर्माण के लिए दिए गए राशि से आवास नहीं बना रहे हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित करते हुए, अंतिम समझाइश दी गई। कार्य समय पर नहीं करने पर देय राशि वापस करने की भी बात कही गई।

जिले के 2080 आंबा केंद्र में किया गया वजन त्यौहार का शुभारंभ

18 तक होगा आयोजन, बच्चों के पोषण स्तर का किया जायेगा आकलन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सोमवार को जिले में संचालित 2080 आंगनबाड़ी केंद्र में वजन त्यौहार का शुभारंभ किया गया। जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर के सटीक आकलन हेतु समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ आंगनबाडी केंद्र में बच्चों का वजन किया जा रहा है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश के अनुपालन में 09 से 18 फरवरी तक चलने वाले वजन त्यौहार के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। ज्यादा से ज्यादा पालक पहुंचे इसके लिए मुनादी व दिवाल लेखन के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी कराया गया हैं। कलेक्टर ने जिले के 06 वर्ष तक के सभी बच्चों के पालकों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र में लेकर आएं और वजन त्यौहार में

सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों के पोषण स्तर की सही जानकारी प्राप्त हो सके और वास्तविक आंकड़ो एवं तथ्यों के आधार पर कुपोषण मुक्त सूरजपुर बनाने के लिए आवश्यक पहल की जा सकें। वजन त्यौहार के दौरान बच्चों का वजन, लंबाई एवं ऊँचाई मापी जा रही है। इसके साथ ही प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रत्येक बच्चे की जानकारी निर्धारित सॉफ्टवेयर में दर्ज की जा रही है। इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे उनके लिए लक्षित पोषण एवं स्वास्थ्य हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि सुपरवाइजर, कलस्टर में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कर वजन त्यौहार का आयोजन करा रही है। इसके साथ ही पालक भी वजन त्यौहार को लेकर उत्साहित है और कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय जनप्रतिनिधि व क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहें है।

वर्ष 2026 का पहला नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वाधान में, वर्ष 2026 का पहला नेशलल लोक के सफल एवं प्रभावी आयोजन को सुनिश्चित करने आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण लोक अदालत की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारीयों एवं समस्त बैंक प्रबंधकों के साथ गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती विनीता वार्नर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री मानवेन्द्र सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, श्री आनंद प्रकाश वारियाल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुश्री पायल टोपनो, नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग के अधिकारीगण तथा जिले में संचालित समस्त बैंक प्रबंधक उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2026 का यह पहला नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। उन्होने नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग के अधिकारीगण तथा जिले में संचालित समस्त बैंक प्रबंधकों को लंबित प्रकरणों, प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित कर अविलम्ब प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए एवं ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निवारण हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करने पर जोर दिया। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने हेतु गहन चर्चा की गई कि संबंधित विभागों द्वारा बकाया राशि, ब्याज और जुर्माने पर वास्तविक एवं प्रभावी छुट प्रदान किये जाए, ताकि जनता को अधिकतम वैधानिक राहत मिल सके।

जिले वासियों से अपील है कि 14 मार्च 2026 के नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर इस नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं।

14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिले के सभी न्यायिक क्षेत्राधिकारों में किया जाएगा, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं जिले के समस्त अनुविभागीय और तहसील न्यायालय शामिल हैं।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

एसएसपी ने अपराधों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने दिया जोर

राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना-चौकी प्रभारियों के साथ बैठक में दिए कई निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने राजपत्रित पुलिस अधिकारियों सहित थाना, चौकी प्रभारियों की पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक लेकर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने जोर दिया।

डीआईजी एवं एसएसपी ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट प्रणाली (एनएएफआईएस) में फिंगरप्रिंट इंट्री बढ़ाने सहित जिला बदर, वारंटियों, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश एवं आदतन अपराधियों का एंट्री अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। ई-चालान एवं ई-साक्ष्य के उपयोगिता की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। थाना/चौकी प्रभारियों को वाहन दुर्घटना के मामलों मे आईरेड में एंट्री हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और विवेचकों को साप्ताहिक डायरी लेखन करने कहा गया। अपराधों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम में थानावार लंबित अपराध, चालान, शिकायत, मर्ग की जानकारी थाना, चौकी प्रभारियों से प्राप्त कर समीक्षा की गई, साथ ही म्यूल एकाउंट एवं पीओएस के लंबित मामले मे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विवेचकों को प्रकरण को अनावश्यक लंबित नहीं रखने की समझाईस दी गई। बैठक के दौरान थाना/चौकी प्रभारियों को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट प्रणाली में एंट्री बढ़ाने एवं गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने निर्देशित किया गया। इसके अलावा अपने-अपने थाना/चौकी अंतर्गत निवासरत निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश, आदतन बदमाश एवं अन्य आपराधिक किस्म के व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट लेकर सिस्टम में अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। सड़क हादसों में कमी लाने एवं हादसों के पश्चात सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा सहित घायलों के इलाज की व्यवस्था हेतु तैयार इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस की इंट्री की समीक्षा करते हुए इसे अद्यतन रखने कहा गया। विवेचकों को आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और न्यायालय में साक्ष्य मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए साप्ताहिक केस डायरी अनिवार्य रूप से लिखने की हिदायत दी गई है। समीक्षा बैठक मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, उप पुलिस अधीक्षक राकेश बघेल, उप पुलिस अधीक्षक अजाक सुरेश भगत, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण तूल सिंह पट्टावी, रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, स्टेनो फबियानुस तिर्की, समस्त थाना/चौकी प्रभारी, रीडर अमित पाण्डेय एवं पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मास्टरमाइंड जूनियर्स स्कूल ने वार्षिक खेल दिवस पर हॉकी स्टेडियम में किया उत्साहपूर्ण आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के चोपड़ापारा स्थित मास्टरमाइंड जूनियर्स स्कूल का वार्षिक खेल दिवस स्थानीय हॉकी स्टेडियम में उत्साह और उमंग के माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकों की खेल विधाओं में सक्रिय सहभागिता ने कार्यक्रम को और आकर्षक बना दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ की गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत कर अनुशासन, एकता और टीम भावना का परिचय दिया। विद्यालय के प्राचार्य मृत्युंजय पांडेय ने खेल ध्वज फहराकर खेल दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथि संजय पांडेय, प्राचार्य एवं अभिभावकों द्वारा मशाल प्रज्वलित कर तथा गुब्बारे छोड़कर वार्षिक खेल दिवस की खेल विधाओं की औपचारिक शुरुआत की गई।

खेल स्पर्धाओं में मेढ़क दौड़, बतख चाल दौड़, बोरा दौड़ सहित विभिन्न एथलेटिक गतिविधियां आयोजित की गईं। इसके अलावा गुब्बारा संतुलन, चम्मच दौड़ और कोन संतुलन जैसे मनोरंजक खेल आकर्षण का केंद्र रहे। अभिभावकों, शिक्षक-शिक्षिकाओं और दर्शकों की तालियों और उत्साहवर्धन के बीच बच्चों ने ऊर्जा, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। अभिभावकों के लिए भी कई प्रकार के मनोरंजक खेल आयोजित किए गए। प्राचार्य मृत्युंजय पांडेय ने कहा कि खेल गतिविधियां बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना है, ताकि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित हो सके। कार्यक्रम के समापन पर वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित किया गया।

अधिकारी अवकाश में जाने से पूर्व लें अनुमति, बिना सूचना अनुपस्थिति पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अवकाश में जाने से पूर्व अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाए, आदेश का पालन नहीं करने वाले एवं बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारी समय-सीमा की बैठक में आने से पूर्व अद्यतन विभागीय जानकारी लेकर आएं तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों की प्रगति एवं क्रियान्वयन की जानकारी भी उपलब्ध करवाएं। बैठक में कलेक्टर ने अपार आईडी में बच्चों की एंट्री की जानकारी ली तथा शत-प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने कहा इस हेतु बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, इसलिए शिक्षा विभाग सर्वे कर जल्द से जल्द ऐसे बच्चों की सूची जिनका जन्म प्रमाणपत्र नहीं बना है, संबंधित अनुभाग के एसडीएम को उपलब्ध कराएं। बैठक में उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टों का नामांतरण महत्वपूर्ण है, इसलिए राजस्व एवं वन विभाग एक माह के भीतर फौती नामांतरण पूर्ण कर लें। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को आश्रम छात्रावासों के निरीक्षण हेतु अधिकारियों की ड्यूटी आदेश बनाने निर्देशित किया। सभी एसडीएम को लगातार छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। छात्रावासों में खेल सामग्री प्रदान करने कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी से पीडीएस दुकानों में राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि समय पर व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करें। बैठक में डीएमएफ अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती, पीवीटीजी युवाओं को रोजगार की जानकारी ली गई। बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल,

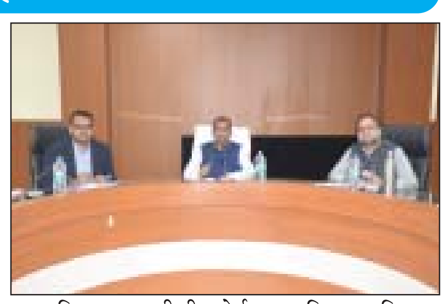

जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि पर विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, राम सिंह ठाकुर, अमृत लाल ध्रुव, नगर निगम कमिश्नर डीएन कश्यप, सभी एसडीएम एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

धान उठाव में तेजी लाने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी उपरांत उपार्जन केंद्रों से धान उठाव की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धान उठाव में तेजी लाते हुए 28 फरवरी तक उठाव पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गम्भीरतापूर्वक भौतिक सत्यापन करवाएं।

मैनपाट महोत्सव में मुख्यमंत्री का आना प्रस्तावित

बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने मैनपाट महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का जिले में आगमन प्रस्तावित है, इसलिए सभी तैयारियां गुणवत्तापूर्ण ढंग से जल्द पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने विभागों को लोकार्पण, भूमिपूजन की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं विभागीय स्टॉल एवं हितग्राही सामग्री वितरण की भी जानकारी प्रदान करने कहा। उन्होंने डोम निर्माण की प्रगति, मंचीय व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलाकारों हेतु व्यवस्था, आमंत्रण कार्ड, साज-सज्जा, लाइट, साउंड सिस्टम, पेयजल, चलित शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की।

अस्पताल के सामने घंटों बेसुध पड़े युवक की किसी ने नहीं ली सुध, हो गई मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने एक अज्ञात युवक घंटों पड़े रह गया, अस्पताल के तमाम लोगों की आते-जाते नजर बेसुध पड़े युवक पर पड़ी, लेकिन उसे उपचार सुविधा मिल सके, इसकी किसी ने सुध नहीं ली, और उसकी मौत हो गई। मृत युवक का शिनाख्त नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को मर्च्युरी में रखवा दिया है।

जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मातृ एवं शिशु अस्पताल के सामने नाली के पास 30-35 साल का एक युवक रविवार से ही बेसुध स्थिति में पड़ा था। इस पर अस्पताल से आने-जाने वाले लोगों और राहगीरों की नजर पड़ती रही, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बताया जा रहा है कि घुमंतू जीवनयापन करने वाले उसके इर्द-गिर्द गए, तक तक उसकी सांस चल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे वह शराब के नशे में सो रहा हो। ठंड भरी रात में युवक उसी हालत में पड़े रह गया। गस्त में निकली पुलिस की भी नजर उस पर पड़ी होगी, लेकिन उसे किसी ने कम्बल तक नहीं ओढ़ाया, और न ही अस्पताल परिसर में स्थित धर्मशाला या अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार को सुबह तक उक्त युवक की सांस थम गई थी और पूरा शरीर अकड़ गया था। एमसीएच परिसर के सामने पड़े युवक की सांस नहीं चलते देख संदेह होने पर इसकी सूचना अस्पताल के पुलिस सहायता केंद्र में दी गई। पुलिस ने मृतक का पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल के मर्च्युरी में रखवा दिया है, और सोशल मीडिया व जिले के विभिन्न थाना, पुलिस चैकी तक मृतक की तस्वीर को वायरल कर दिया है, ताकि उसकी पहचान हो सके। इधर अस्पताल के सामने लावारिस हाल में पड़े युवक की मौत को लेकर लोगों का कहना है कि मानवता के नाते अगर युवक को समय रहते उपचार की सुविधा सुलभ कराई गई रहती, तो उसकी जान बच सकती थी।

सरगुजा ओलम्पिक अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता आज से

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बस्तर ओलम्पिक के सफल आयोजन के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस वर्ष सरगुजा ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं तथा 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष प्रतिभागी 12 विभिन्न खेल विधाओं में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तृतीय चरण में जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो सभी जिला मुख्यालयों में संपन्न होंगे। विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी जिला स्तर पर भाग लेंगे, जबकि हॉकी एवं कुश्ती के पंजीकृत खिलाड़ी सीधे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों में फरवरी माह के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित किए जा रही हैं। अंबिकापुर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता 10 से 12 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। जिला स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशासन द्वारा परिवहन, भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 2000, 1500 एवं 1000 की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। दलीय खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीमों को क्रमशः 4000, 3000 एवं 2000 की पुरस्कार राशि के साथ प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जिला स्तरीय आयोजन हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। चौथे एवं अंतिम चरण में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन मार्च माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है।

आदिवासी समाज किया चक्काजाम, लिखित आश्वासन के बाद एनएच से शुरू हुआ आवागमन

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। सोमवार को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने जामवंतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर सांकेतिक चक्काजाम कर दिया। भूमि सीमांकन की लंबित कार्रवाई और प्रशासनिक उदासीनता से आक्रोशित आदिवासी समाज ने यह कदम उठाया। मौके पर पहुंचे रामानुजगंज तहसीलदार द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद जाम को समाप्त कराया गया। जानकारी के मुताबिक, जामवंतपुर निवासी सतन पिता स्व. अठली के नाम से दर्ज भूमि के सीमांकन हेतु 10 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार न्यायालय रामानुजगंज द्वारा आदेश पारित किया गया था, आदेश के कई माह बीत जाने के बाद भी आज तक भूमि का सीमांकन नहीं हो सका। इस बीच उक्त भूमि की सीमा पर कुछ लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न कर मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे आवेदकगण मानसिक रूप से परेशान और निराश हैं। इसी बात को लेकर कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर के नेतृत्व में बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके जब जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब समाज ने मजबूर होकर सोमवार दोपहर सांकेतिक चक्काजाम कर विरोध दर्ज कराया। समाज प्रमुखों ने आरोप लगाया कि जामवंतपुर क्षेत्र में स्टे ऑर्डर के बावजूद कई स्थानों पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति से भली-भांति अवगत होने के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा जब स्वयं अधिकारियों द्वारा जारी स्टे आदेशों का पालन नहीं कराया जा रहा, तो भू-माफियाओं के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। तहसीलदार के आदेशों का पालन न होना और पटवारी स्तर पर उदासीनता प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। समाज ने स्पष्ट कहा कि यदि जिम्मेदार अधिकारी समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते, तो आदिवासी समाज को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर सात दिवस के अंदर भूमि का सीमांकन नहीं होता है तो आठवें दिन समाज रामानुजगंज तहसील कार्यालय का घेराव और विरोध प्रदर्शन करेगा।

बेंगलुरू में सरगुजा की बेटियां दिखाएंगी अपनी प्रतिभा

ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल महिला चैंपियनशिप के लिए टीम रवाना

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की महिला बास्केटबॉल टीम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल महिला चैंपियनशिप में भाग लेने हेतु बेंगलरू के लिए रवाना हो चुकी हैं। यह प्रतियोगिता 10 से 14 फरवरी तक जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की टीम में सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के नियमित खिलाड़ी शामिल हैं, जो गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में नियमित अभ्यास करते हैं। सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ से विश्वविद्यालय टीम में प्रज्ञा मिश्रा, रिविका लकड़ा, रिमझिम, साक्षी, प्रिया जायसवाल, सुष्मिता, प्रियंका पैकरा, संसिता, रागिनी, प्रीति, नेहा एवं आकांक्षा का चयन किया गया है, जो विश्वविद्यालय के टीम कोच रजत सिंह एवं मैनेजर राधा खलखो के नेतृत्व में प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर में सरगुजा जिला बास्केटबॉल, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय परिवार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

कलेक्टर ने बैठक में की प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को ग्रामीण आवास योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जनमन आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 32,195 आवासों में से 18,262 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष अपूर्ण आवासों को माहवार लक्ष्य के अनुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाए। साथ ही 5,487 अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनमन आवास योजना की समीक्षा में बताया गया कि स्वीकृत 2,565 आवासों में से 1,371 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवासों में से 524 को 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की ली प्रथम बैठक आयोजित

औद्योगिक विकास हेतु विभागों से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिले में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एजेंडावार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, बिजली, और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाएं। मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैठक में औद्योगिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंडा प्रस्तुत किया गया। इसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जिला पंचायत विभाग से औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न स्वयं सहायता समूहों का विवरण। वन विभाग में वनोपज उत्पाद एवं प्रसंस्करण की संभावनाएं। कृषि एवं जल संसाधन से फसलों की उत्पादकता, सिंचित क्षेत्र और जलाशयों की क्षमता। विद्युत एवं लोक निर्माण से बिजली की उपलब्धता (निम्न/उच्च दाब) और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं अंतर-जिला सड़कों का नेटवर्क। खनिज एवं श्रम से गौण खनिज के क्षेत्र और श्रम कल्याण से संबंधित डेटा। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप औद्योगिक परियोजनाओं के लिए स्थानीय प्रशासन से मिलने वाले अनुमोदनों को सरल और त्वरित बनाने पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी विभागीय सदस्यों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी शीघ्र जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को उपलब्ध कराएं, ताकि जिले में निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार हो सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर